(श्री अटल बिहारी वाजपेयी)

है। आप ने सदन की भावना देखी कि हम लोग अधिक से अधिक समय चाहते हैं। मंत्रालयों की माँगों के ऊपर चर्चा के लिए समय निकल सकता है अगर आप भोजन की छुट्टी समाप्त कर दें और शनिवार को भी सदन बैठना आरम्भ कर दें। समय निकाला जा सकता है और इस बारे में आप सदन की राय ले लीजिए।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : किसी भी मिनिस्ट्री की बजट डिमांड गिलोटिन नहीं होनी चाहिए। सब पर सदन में विचार होना चाहिए।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): Sir, we do not have Members present in the House to discuss the demands. There are hardly twenty Members present in the House.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, we are prepared to sit upto 7 'O' clock. I can assure you that on behalf of my party I am prepared to sit here upto 7 'O' clock unless of course I leave Delhi on some business. Further longer hours will definitely affect our efficiency. This has already affected our efficiency. Unless we do away with the lunch hour and work on Saturdays also, the work would not be completed. Otherwise, it may be decided to have two shifts—day and night shifts.

अध्यक्ष महोदय : कल बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा यह लँच औवर को सस्पेंड करने की बात नहीं मानी गई थी। हम उसका कोई और हल सोचेंगे, किसी शनिवार को ले लेगें या फिर शाम को थोड़ा और अधिक तक बैठ जायेंगे। अब बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी दुबारा इस पर निर्णय कर सकती है। अभी तक तो वह यह भोजन की बीच की छुट्टी खत्म करने के लिए मानी नहीं है। अब आप लोग वहाँ तो कहते नहीं हैं यहाँ हाउस में कहते हैं तो उससे फायदा क्या है।

The question is:

"That this House do agree with the Fortyeighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th April, 1970."

The motion was adopted.

SHRI RAGHU RAMAIAH: May I make one submission? Since the Business Advisory Committee and the House have agreed to take up the Bill on the 23rd, the House may sit to consider this Bill from 6 P.M. to 8 P.M. on the 23rd.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): What is to be taken up on the 23rd.

MR. SPEAKER: A Bill about Bengal will be taken up.

श्री जी० वेंकट स्वामी (सिद्दिपेट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के नोटिस में एक मामला लाना चाहता हूँ। करीब 40 रोज से हैदराबाद में सिंथैटिक ड्रग्स फैक्टरी में हड़ताल चल रही है। यह फैक्टरी हमारे पब्लिक सैक्टर में है और यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि वहाँ इस फैक्टरी में पिछले 40 रोज से हड़ताल चल रही है और मिनिस्टर महोदय इस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने एक कौलिंग अटैंशन नोटिस भी दिया हुआ है। यह पबलिक सैक्टर की अंडरटेकिंग है और इस तरह से वहाँ पर 40 रोज से हड़ताल चल रही है। कम से कम अध्यक्ष महोदय, आप अवश्य इस बारे में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाइये...

MR. SPEAKER: I do not allow you. Please sit down.

SHRI S. KUNDU (Balasore): This is a serious matter. Thousands of workers are on strike.

Mr. SPEAKER: There are other ways of discussing it. Do not come here at any time to raise it abruptly.

12.35 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS, 1970-71—*contd.*

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS—(*contd.*)

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं परसों कम्पनी ला में हेर फेर की बात कर रहा था। एक दूसरा उस में संशोधन हुआ है और वह यह कम्पनीज के लिए किसी भी पोलिटिकल पार्टी को चन्दा देना अब गुनाह करार दिया गया है। मेरे सामने एक

*Moved with the recommendation of the President.

जबरदस्त नमूना है । यह एक किताब है जो कि तथाकथित कांग्रेस सेशन जो बम्बई में किया गया था पिछले दिसम्बर में उसकी यह सौवनीर कही जाती है । उसमें लिखा हुआ है कि ऐडवरटिजमेंट के लिए 2500 रुपये फी पन्ना चार्जेज है। मगर मेरी खबर यह है कि 2500 रुपये से बेशी बहुतों ने दिया है और उनसे इस से बेशी लिया गया है । अब 2500 से एक रुपया भी ज्यादा लिया गया है हालांकि खबर तो यह है कि 20 गुना तक ज्यादा उन से लिया गया है। तो वह फाजिल रुपया चन्दा हो गया। क्योंकि वह शैडयूल्ड रेट से ज्यादा हो गया । अब इसका पता लगा कर बतलायें कि किस कम्पनी से कितना बेशी लिया है ?

दूसरी बात यह है कि अगर आप कहें कि यह चन्दा नहीं है बल्कि यह ऐडवरटिजमेंट है तो इसमें करीब 15 मामले ऐसे हैं जो कि ऐडवरटिजमेंट किसी कायदे से कहे नहीं जा सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आप उन्हें ऐडवरटिजमेन्ट किस कायदे से कह सकते हैं? उस में लिखा है : "विद दी बेस्ट कम्प्लीमेंटस फ्रौम ए वैलविशर ।" अब जब वैलविशर का नाम ही नहीं मालूम तो विज्ञापन क्या हुआ और उस का पैसा काहे को दिया गया ? अगर वह पैसा दिया गया तो यह चंदा नहीं है तो फिर और क्या है ? अब यह पता लगाना आप का काम है बशर्ते कि सरकार लगाना चाहे । अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी मदद करेंगे बशर्ते कि आप पता लगाने को राजी हो जांय । असलियत यह है कि वह चन्दा नहीं है बल्कि वह ऐक्सट्रैक्शन है । वह एक तरह से चौथ है जो कि मराठे वसूल किया करते थे । यह भी मराठों की नगरी बम्बई में उन्हीं की चौथ के समान है । इस चीज के बारे में आप को इनक्वायरीं करनी होगी नहीं तो बतलायें कि यह लिया कैसे ?

दूसरी बात यह है कि आप की मिनिस्टरी में इंटरनल ट्रेड भी है । इंटरनल ट्रेड में आप ने क्या किया ? दो नमूने मैं बतलाऊंगा । ज्यादा बतलाने के लिए मेरे पास समय नहीं है । एक तो अचानक एक दूसरे जरिये से मुझे यह चीज मिल गई और वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की आडिट रिपोर्ट डिफेंस सर्विसेज की है । मै डिफेंस मिनिस्टरी की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भाग लेने जा रहा था और वह रिपोर्ट मैंने पढ़ी । उस आडिट रिपोर्ट में देखने से यह पता चलता है कि मैसर्ज इन्डियन कौपर कारपोरेशन से 4300 टन एलैक्ट्रोलिटिक कौपर लिया गया 27 फरवरी, 1967 को उसका रेट 7400 रुपया फी टन तय पाया गया था मगर उसके थोड़े हीं दिनों बाद जब कि वर्ल्ड मारकेट रेट में करीब 8370 रुपया फी टन था आप के यहां दूसरा आर्डर दिया गया डाइरेक्टर जनरल आफ सिविल सप्लाईज की ओर से मिनिरल एंड मैटल्स ट्रेनिंग कारपोरेशन के यहाँ अप्रैल, मई, 1967 में सिर्फ 12100 रुपये फी टन की दरसे 3159 टन का जब कि बाजार हिन्दुस्तान का रहा 7400 फी टन और वर्ल्ड मार्केट में रहा 8370 फी टन का । आप के यहाँ रहा 12100 और वह भी 92 रुपया फी टन घाटे पर। यह रहा आप का इंतजाम ।

दूसरा इंतजाम जो मुझे मालूम हुआ है उसका भी एक नमूना मैं दे रहा हूँ। नमूने से मेरे पास अधिक समय बतलाने को है भी नहीं। 19 दिसम्बर तक आप बहुत जोरों से कहते रहे कि सीमेंट की कमी देश में नहीं है इसलिए वह पहली जनवरी से डिकंट्रोलकर दिया जायेगा लेकिन 22 दिसम्बर को आपने कह दिया कि वह डिकंट्रोल नहीं होगा और सीमेंट पर कंट्रोल चालू रहेगा। 22 दिसम्बर से आज लगभग 4 महीने हो गये लेकिन अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया कि आप की पालिसी क्यों बदली और कैसे बदली । अब इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य है यह राजनीति को समझने वाले समझ सकते हैं। वह चंदा व्यक्ति का है बाकी इंडस्ट्रीज का तो है ही । मगर यह चंदा एक और भी है जिसकी कि वजह से यह गवर्नमेंट बची है। डी एम के को राजी करने का प्रयत्न हैं क्योंकि उसके फायदे की बात और मद्रास के फायदे की बात है। सीमेंट इतनी भारी चीज है कि उसे दूर नहीं ले जाया जा सक ता है। उसकी बिक्री उसके आस-

(श्री मृत्युंजय प्रसाद)

पास में होती है और दूर के नाम पर जो थोड़ा सा माल भाड़ा उसके ऊपर अधिक पड़ता है अर्थात् उसके ऊपर जो बेशी माल भाड़ा लगता है उससे नाम पर सभी सीमेंट का दाम बढ़ने का बहाना मिल गया इससे उत्तर की अपेक्षा मद्रास की मिलों को सीमेंट के ज्यादा दाम मिलते हैं। अब किसका क्या हिस्सा है यह मैं कैसे कह सकता हूँ ?

यह मैंने इंटरनल ट्रेड के बारे में एक, दो नमूने बतलाये। अब मैं आ रहा हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में जिम्मेंवारी के पद पर काम करने का काफी अच्छा अनुभव रहा है और मेरा दावा है कि वैसा अनुभव बहुत कम आदमियों को होगा। भीतर से रिस्पौंसिविल पोस्ट पर रह करके, पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर, इन दोनों का अनुभव बहुत कम आदमियों को होता है। एक का अनुभव तो हो सकता है चाहे इसका या उसका। मैं इस हिसाब से आप से कह रहा हूँ कि पब्लिक सेंक्टर में जो काम आप ने किये हैं वह बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छी नीयत से काम शुरू किए गये हैं, मगर हालत वही है जैसी कहावत है कि अनाड़ी के हाथ में माल पड़ जाय तो उसकी दुर्गति हो जाती है, जैसे कि बनाने चले गणेश की मूर्ति, लेकिन बन गया कुछ और क्योंकि बनाना आता नहीं है। और इसके नमूने एक नहीं हजारों हैं।

अभी दिसम्बर में प्रधान मंत्री ने प्रो० घर और मि० चोपड़ा को इंटरव्यू दिया था। वह छपी है आप के "लोक उद्योग" में। उसमें उन्होंने बहुत समझाया और तीन कारण बतलाये खास तौर पर कि हम क्यों पब्लिक सेक्टर में घाटे की परवाह नहीं करते। एक तो यह चीज इसलिए बनाई गई कि उसको दूसरे करने को राजी नहीं हैं, दूसरी बात यह कि इससे हम सोशल प्राफिट्स पाते है और तीसरी बात यह है कि हम रीजनल इम्बैलेंस कम करते हैं। मैं तीनों के बारे में कहूँगा कि आप की आज हालत यह है कि जो आप के सेक्रेट्री बनाकर रख देते हैं, लिखकर देते हैं, उसको आप तोते की तरह पढ़ देते हैं। खुद तो समझते बहुत कम हैं, और उसकी वजह है—क्षमा कीजिए मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं—मिडियोकर मिनिस्टर और ब्रिलिऐंट सेक्रेट्री हों तो इसके सिवा और होगा क्या। अब मैं इस पर आ रहा हूँ कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ।

यहाँ उदाहरण रक्खा गया है आयरन का, लेकिन हमारी प्रधान मंत्री भूल जाती है, मंत्री महोदय भूल जाते हैं कि यहाँ स्टील फैक्ट्री पहले पहल शुरू हुई 19 वीं शताब्दी में, 20 वीं शताब्दी में नहीं। उसके बाद टाटा ने खोला टिस्को (TISCO) उसके बाद खुला आई एस सी ओ, फिर भद्रावती। इन सबकी हालत यह है कि पिछली लड़ाई के समय 1942-43 के लगभग बहुत ही सस्ता दाम था स्टील का और क्वालिटी भी अच्छी थी। आज क्या हालत है? उस समय टाटा ने कहा एक्सपैंड करने के लिए लेकिन आप ने एक्स्पैन्शन को रोक दिया, इस ग्राउंड पर कि तुम्हारे पास जो पैसा आता है वह तुम उसमें प्लाऊ डाउन नहीं कर सकते, वह तुमको शेअरहोल्डर्स में बाँटना होगा। नतीजा यह हुआ कि दाम बढ़ते रहे शेअर्स के और उसको शेअरहोल्डर्स में बंटवा दिया गया। उन्हें एक्स्पैंड करने में बाहर का कैपिटल नहीं लग सका। नतीजा यह हुआ कि जिस वक्त सस्ते में एक्स्पैंशन हो सकता था, वह नहीं कर पाये और आप ने मंहगे में किया। आज जो आप कर रहे हैं अगर उसकी कथा कही जाय तो हिन्दुस्तान स्टील लाभ की चीज नहीं है लेकिन उसमें कई करोड़ डूब चुके हैं। उसमें शेअर कैपिटल है 552 करोड़ और 162 करोड़ आप ने डुबा दिया। फिर भी हालत जो है वही चलेगी। वह सुधरने वाली नहीं है। फिर भी हर साल आप अपने कारखाने के घाटे को कम करने के लिए इस्पात का दाम बढ़ाते जाते हैं और उस बढ़ती का लाभ

मिलता है टाटा और दूसरी निजी क्षेत्र की कंपनियों को, उनके हिस्सेदारों को और मारे जाते हैं गरीब करदाता तथा खरीदार। यही सोशल प्राफिट है।

इसके साथ साथ आपने बोकारो शुरू किया। उसमें आप ने कई सौ करोड़ रुपये लगाये और कई सौ करोड़ और लगाइयेगा। उस बोकरो की आज क्या हालत है? उसकी हालत आज यह है कि हैवी इंजीनियरिंग की कृपा से और हैवी प्लेट्स की कृपा से कहा जाता है कि 25 लाख रोज का घाटा होता है और कोई कहता है कि 1 करोड़ रु० का घाटा होता है, कोई कहता है कि अब तक 105 करोड़ का घाटा हो गया है और बढ़ता जायेगा। इसलिए इसमें देर हो रही है।

इधर हेवी इंजीनिअरिंग तो आप की चीज है, उस के रोने की कौन सी बात की जाय? 100 करोड़ की पूंजी में 41 करोड़ घाटे में स्वाहा हो चुके। इन सब के पीछे क्या कारण हैं? अनाड़ीपन है या और कुछ है? मैं इस अनाड़ी पन के दो-एक उदाहरण आप के सामने रक्खूंगा। पहली चीज यह है कि आपने योजना बनाने में कभी यह नहीं सोचा कि वह योजना किस के लिए बना रहे हैं इस चीज की बिक्री होगी या नहीं होगी। मिनिस्ट्री का रोना है कि हम को नई फैक्ट्री बनानी है, उधर मोटर वालों का रोना है कि उनको इस क्वालिटी की चादरें नहीं मिलतीं जिससे वह गाड़ियों की बौडी बना सकें। इसलिए ये चादरें जापान से मंगाई जाती हैं। आज छोटी से छोटी चीज बाहर से इम्पोर्ट की जाती है जैसे सेफ्टी ब्लेड बनाने वाला स्टील, रेजर ब्लेड बनाने वाला स्टील। ऐडवर्टाइजमेंट निकलता है कि हम इम्पोर्टेड स्टील से बनाते हैं, जैसे कि हिन्दुस्तान में अक्ल ही नहीं कि वह हजामत की पत्ती के लिए अच्छा इस्पात बना सके। दूसरी तरफ हालत यह है कि आपकी कपैसिटी युटिलाइज नहीं होती है। आप ने आसमान तक उसको बढ़ा दिया और पूरी कपैसिटी आप की युटिलाइज नहीं होती। क्यों नहीं होती, यह आप से कौन पूछे? वजह यह है कि यहां पब्लिक का पैसा लगा दिया जाता है और वहां आप ने बिठला दिया है आई सी एस को या वैसे पालिटीशियन को जिनके लिए दूसरी कोई जगह नहीं है जो इलेक्शन बार-बार हारे हुए हैं। उनसे बचे तो आप किसी दूसरे को दीजिये। नतीजा यह है कि जैसा वह आप को समझाते हैं वैसा आप करते हैं। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती, और फिक्र करके वह क्या करेंगे, जितना रुपया घटेगा वह उनको यहाँ से हिन्दुस्तान के करदाताओं से मिलेगा।

अब मैं एक ही बात कह कर खत्म करूंगा। आप को यह भी सोचने की दरकार थी कि हमारी जो प्लैनिंग हो वह फ्यूचर डेवेलपमेंट कंट्री का कैसे हो उसके मुताबिक होना चाहिये। हिन्दुस्तान में आबादी बढ़ेगी और उसके मुताबिक लोगों को सब चीजों की दरकार होगी। उसके हिसाब से आप को सब कुछ करना चाहिये था, लेकिन वह तो आप ने किया नहीं क्योंकि आप ने मान लिया कि डा० चन्द्रशेखर का निरोध बहुत ही सफल होगा, और बढ़ने के बदले आबादी घट जायेगी। बहुत कम सामान बनाने से काम चल जायेगा। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका निरोध तो सफल रहा नहीं, आप का औद्योगिक निरोध बहुत सफल हो गया। इसलिये मैं कहूंगा कि आप की मिनिस्ट्री के नाम तो बहुतों ने रक्खे है, लेकिन अगर आप आगे से उसका नाम औद्योगिक निरोध रक्खे तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

आप को मैं एक नमूना बतला कर समाप्त करना चाहूँगा कि किस तरह से हिसाब किताब में गड़बड़ी होती है और उस को किस तरह छिपाया जाता है। मेरे हाथ में "जर्नल आफ इन्डस्ट्री ऐण्ड ट्रेड" है जो आप की ही मिनिस्ट्री की चीज है। उस में भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स के बारे में दिखलाया गया है कि 1968–69 तक क्यूमुलेटिव लासेज 16·4 करोड़ के हुए। मगर हमें भुलावा देने के लिए उस को इस तरह से बतलाया है।

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

कि अगर एलिमेंट आफ डिप्रेशन को आमदनी मान लिया जाय और उसको उसमें से कम कर दिया जाय, उसके बाद गवर्नमेंट लोन्स पर जो इंटरेस्ट दिया गया है उसको काट दिया जाये तो इतना बड़ा घाटा बदल कर क्यूमुलेटिव प्राफिट हो जाता है 1 करोड़ 48 लाख का। क्या आप इसी हिसाब को सही मानते हैं? अगर आप इसी हिसाब को सही मानते हैं तो यह आँख में धूल झोंकना होगा। फिर अगर आप इस हिसाब को सही मानते हैं तो क्या आप इस 1 करोड़ 48 लाख रु० पर इनकम टैक्स देने के लिए राजी हैं? अगर यही हिसाब आता है आप के यहां तब फिर मै क्या कहूं। उनकी रिपोर्ट इस तरह आती हैं और आप का हिसाब इस तरह से आता है।

इससे बाद में अब रीजनल इम्बैलेंस की बात पर आता हूं। आप असम से लेकर कश्मीर तक चले जाइये। हिमालय की तराई और तलहटी छोटी नहीं हैं। यहां कौन सी इंडस्ट्री आप ने शुरू की है? सिर्फ शुगर, प्लाई वुड, या दियासलाई की काठी बनाने का काम, जिनमें सब चीजें सोलह आने ऐग्रीकलचर पर निर्भर करती हैं। आप ने वहाँ बनने क्या दिया है? कुछ राईस मिलें बनाई हैं असम में इसके अलावा और आप ने क्या किया है? रीजनल इम्बैलेंस और किस को कहते हैं? और मैं यह एक प्रदेश की बात नहीं कहता हूं।

कर्ज लेकर यों होली खेलने का जो काम आप करते हैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ :

कर्ज को पीते थे मै और समझते थे कि हाँ,
रंग लाएगी यह फाकामस्ती हमारी एक दिन।
यह गालिब समझते थे, लेकिन सरकार समझती है या नहीं, मै नहीं जानता।

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor): Mr. Speaker... (*Interruptions.*)

MR SPEAKER: Other Members who are to precede him are not present; so I have called him.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): He has the monopoly of speaking on every debate; they have no other speakers.

SHRI BEDABRATA BRUA: I was much lower down but some of the speakers are not here and so I was called to speak.

I think the basic document on the industrial policy of the Government is the Dutt Commitee's recommendations which went into the question of monopolies and devised certain effective norms by following which concentration of monopolistic and economic power can be held in check. I fully agree with the recommendations of the Dutt Committee and I believe that the Cabinet resolution of February 17 or 18 which tries to implement the recommendations of the Dutt Committee by and large is a step in the right direction. This Dutt Committee's division of industries into the core of heavy investment sector, middle, sector and unlicensed sector is, by and large, a very proper classification. As the Dutt Committee recommended that in the heavy investment sector alone, monopolies can really grow,—and monopolies also can grow in the middle sector—something should be done in terms of regulations to control the growth of monopolies by insisting, first of all, that in the middle sector there should be no encroachment of big business-houses, and in the heavy investment sector big business-houses should be allowed, because of their financial ability and all that, to participate. But, at the same time, it added a proviso—and it is a very good idea—that the big business-houses should not in any case be allowed to fatten at the cost of the public financial institutions and the nationalised banks, as the banks were nationalised later on. So, the Government should consider it as a joint sector. That is the core of the Dutt Committee's report: that the entire core sector, the heavy investment sector, should be considered as a joint sector, and when loans are given to big industries in the industrial sector, the Government should put in a clause the financial institutions and the banks should put in a clause—that the Government reserves the right, the financial institutions have a right, to participate in the management of these industries by purchasing equity shares and converting the loans or other funds which are advanced, into equity shares. While I believe that the Government has accepted this on principle, I would like to know whetsher such instruction

have been issued to the banks and the financial institutions that this clause is introduced, and not merely say that when these industries are in a bad shape the Government might convert their loans, etc. , into equity shares and also try to relieve them of their difficulties: that will not do. Naturally, we expect that the Government would take steps to definitely declare the big industries as the joint sector, and where Government assistance could only come as a participator in the equity shares.

This is very vital. Otherwise, the entire Dutt Committee's report would be rendered completely meaningless, because it is here that vast funds come. The Dutt Committee have gone into the big assets of the Birlas and found that there is concentration of assets and wealth in the form of industries there. Of course, there are only eight or nine or 10 business-houses with about 70 per cent of the total assets. In this question of the monopolies, I would not include just Birlas alone but all such big business-houses must be included, and it is here that the Government participation should come in.

The second point that I would like to emphasise is about the backward areas. There was a Cabinet resolution which was a very welcome resolution in that 10 per cent of the capital would be subsidised by the Government in the backward areas. Then there was another decision that in the backward areas, whenever a decision is made to locate some industries there, income-tax and other taxes would not be imposed for the first five years or something like that. In view of the fact that all the backward areas have been contributing to the development of the advanced areas, this is a must. But I regret that this recommendation has not been accepted by the Chief Ministers' Conference and the NDC. I do not know whether so far as these proposals are concerned they are as good as dead. I would request the Industries Minister to try to revive this and find out measures to develop the backward areas, and not just give expressions of goodwill; we have had enough of such expressions. Though the Planning Commission has been asserting that the backward areas should be developed and concessions should be shown to them in the matter of industries, basically the backward areas have become more and more backward and the advanced areas are developing further. This leads to tensions within the country and the centrifugal tendencies that we see are a direct outcome of these tensions that we see in the country. This is a vital point, such things should not be allowed to develop.

I now refer to the public sector. The Industrial Policy Resolution of 1956 asserted that there would be two Schedules: one Schedule covering all the industries which require a long gestation period requiring a very heavy investment in terms of capital and requiring a new and very complicated technology and a market which may not be created because of the non-advancing industrial sector.

All those industries which would not be able to use their full capacity at a point of time become victims of recession, whenever recession comes. The consumption sector that was left with the private enterprises did not suffer from recession. Air—conditioners or refrigerators did not suffer from recession. Recession came to this sector which was not expected to make a profit and this allowed a handle to opponents of public sector to malign it. After the Industrial Policy Resolution, Government started entering that sector where there is no profit. I want that this Industrial Policy Resolution of 1956 should be further clarified to include the possibility, rather certainty of the Government entering those sectors which are consumer-oriented and export-oriented.

So far as export-oriented industries are concerned, recently the Ministry of Foreign Trade has reportedly made some recommendation licensing requirements with regard to big business houses should not be applied so far as export-oriented industries are concerned. This is one of the biggest faults. It is a misnomer to call them export-oriented industries. For instance, artificial silk industry was recommended this type of treatment by the ministry and licences were given, saying that it would lead to exports. But later on, did the Government care to enquire how many of them really exported their production? All the best textiles which were produced were given for internal consumption because of the heavy demand in the country and the growth of a sort of middle-class, upper salaried class, etc. The real growth of exports was in those industries which were producing cotton textiles of indigenous variety. How long can we go on trying to take a wrong view of things? If export-oriented industries fail to export,

[SHRI BEDABRATA BARUA]

they should be nationalised. I have no doubt that if we are to produce consumer goods for internal consumption, it is an insult to the common man. We should produce consumer goods and luxury goods and they should be exported. If the private sector is not able to do it because of the strong demand for consumer goods in the country and the lop-sided development of economy, we should do something about it.

About the loan policy, there has been always discrimination against the public sector enterprises. It concerns other ministries also. A few months ago, I had occasion to visit the HMT. It produces one of the best watches economically. It produces only 2½ lakhs watches whereas the watches smuggled into India amount to 30 lakhs and the country must have paid at least Rs 100 crores for the smuggled watches. The HMT people told me authoritatively that they have been applying for foreign exchange for expansion, but they are not given the foreign exchange. We have to change the entire idea about loan, foreign exchange and all these things and give high priority to public sector. Nothing should be done to help low priority items in the private sector.

SHRI R. K. BIRLA (Jhunjhunu): Mr. Speaker, I would like to compare this Ministry with an old wife who believes more in 'don'ts' than in 'dos'. The philosophy of 'dont's' adopted by this Ministry retards the industrial growth of this country which we can ill-afford at this time if we are determined to achieve more than 7 per cent rate of growth. I state here what Shri L. K. Jha has stated a few months back about this. He has stated that if the country's economy is to be-improved, we cannot go on with "ifs" and "buts". Therefore, I would suggest that the hon. Minister, Shri Ahmed, should try his best to remove these "don'ts", "ifs" and "buts" if he wants his Ministry to achieve their objects.

MR. SPEAKER: The hon. Member may continue his speech after lunch.

The Lok Sabha adjourned *for Lunch* till Fourteen hours of the Clock.

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT FIVE MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

DEMANDS FOR GRANTS, 1970-71 *contd.*—

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS *contd.*—

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri R. K. Birla to continue his speech.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Sir, I have given a Call Attention notice on the undesirable activities of the American Ambassador, Mr. Kenneth B. Keating, in this country, who has been criticising the Government of India for their decision to close down cultural centres in India. Will you kindly ask the Minister of External Affairs to make a statement as to what they propose to do against the undesirable activities of the American Ambassador in this country, who is anxious to create chaos and trouble in the country.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar): Sir, I have to raise a point of submission which causes a grave concern to all of us, that the house of the Opposition Leader in West Bengal Assembly, Shri Siddhartha Shankar Ray, has been ransacked. It is yet not known which are the parties involved in this. A live bomb had been planted in the library which might have burst any moment and killed his aged mother, and the innocent people in the House. I want the Home Minister to make a statement on this.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): अध्यक्ष महोदय, कल जो बर्दवान में गैंगमैन और आर पी एफ के बीज में क्लैश हो गया था जिसमें गोली चली, गैंगमैन मारे गए और 24 आदमी घायल हुए, इसके बारे में मैंने ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इतना महत्वपूर्ण सवाल होते हुए भी वह माना नहीं गया और मैं आप के जरिए चाहूंगा कि रेलवे मंत्री इसके बारे में कुछ बताएं।

MR DEPUTY-SPEAKER: All that has come in the papers.

SHRI BABURAO PATEL (Shajapur): Sir, this morning, we stood in silence for a short while as a mark of respect to Dr. U. Misra who died. I would suggest that we stand for a minute in prayer for those American astronauts who are coming down to earth from the moon. It will be a good gesture.

MR. DEPUTY-SPEAKER Kindly give a proper notice.

SHRI BABURAO PATEL: This is not a question of giving any notice. Those astronauts are coming down to earth at the moment. Let us stand and pray for their safe return.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We all will be very happy. We shall heave a sign of relief on their safe return to earth. The whole world is concerned about it.

Shri R. K. Birla to continue his speech

SHRI R. K. BIRLA: Mr. Deputy Speaker, Sir, as I was saying in the morning if the Government of India still continues to act on "don'ts, ifs" and "buts", that is going to be very harmful to the country and to the industrial growth.

In 1967-68, we know very well, there was a growth of less than 1 percent which is a matter of deep concern to everyone of us. I feel happy that the Government took some steps as a result of which the industrial growth of the country increased to 6.5 per cent in 1969. If my suggestions are taken seriously by the hon. Minister, Shri F.A. Ahmed, I feel very sure that it is going to increase further and it may be nearabout 8 per cent.

Before I give my suggestions to the Government as to what steps they should take for the development of industrial growth of the country, I would not hestitate to say something about the part played by the private enterprise so far. In spite of the fact which is beyond a shadow of doubt that the private enterprise, on the whole, played a very important role in India's massive economic development for which it certainly requires compliments from all of us.

I am sorry to say one thing. Its reputation and image before the public is rather poor. What is the reason? According to me, there is only one reason for the image and reputation of the private sector being so poor before the public that the trusteeship concept of Mahatma Gandhi was not fully and sincerely kept in view while forging ahead towards economic development of the country. It is certainly a matter of deep concern to all of us. It is said that some of the mills have gone sick and some of the units are going to fall sick. Well, I am sorry to hear about this sickness. Anyone of us will be sorry about the sickness whether it is of mills or humanbeings. I am actually grieved to know that while the units have become sick, the proprietors or the Managing Agents of these sick units have become healthy or even healthier. That is something I cannot understand. Here, I would refer to Mr. J.R.D. Tata's speech delivered a few months back when he said:

> "As a result of the suspicion and hostility which this poor image of the private sector has generated in the minds of Government, public and Parliament, it is being increasingly denied the opportunities to play the full part of which it is capable of in developing the country's economy." As a result many sound projects of importance to the country put forward by honest, competent and resourceful companies are being frustrated to the detriment of the economic development of the country."

Now the question arises: how we can revive this lost image. It is possible only when we take effective steps to follow the trusteeship concept of Mahatma Gandhi. Besides this, my emphasis is that we firmly and sincerely adopt the concept of social responsibility while establishing a unit. By this I mean that business policy should not be dictated by mere laws of supply and demand and only with profit motivations, but we should develop a third dimension which is the welfare of the locality where the mill is situated. It should be the responsibility of the unit to make approach roads, electrify the houses, construct houses, hospitals, schools and dispensaries, etc., say within a radius of about 10-15 miles of the unit. Simply working according to the Companies Act and other Government laws does not mean that we are fulfilling our social objectives. The satisfaction and sense of oneness comes only when the sorrow and happiness, the grief and pleasure of the neighbouring people is closely interlinked with the prosperity and adversity of the unity concerned.

Sir, the Monopolies Act has already been enacted. Therefore, I won't say anything about it. I would certainly say one thing. I am definitely against monopoly, concentration of economic power, concentration of wealth because we know very well that it is against the fundamental principles of socialism. To-day, Sir, every one of us is committed, the country is committed, the Government is committed and we are all committed to socialism. But I would certainly endorse the views of Mr. T. T. Krishnamachari when he said a few months back in Delhi that in the name of monopolies, for heaven's sake, don't restrict the production, don't curb the industrial growth because restricting the production, and curbing the industrial growth is much worse

[SHRI R.K. BIRLA]

and I fully share what Mr. Krishnamachari has said. I hope Government will not think for a moment of putting a spoke in the wheel when somebody is interested in increasing production. I may say, I have no sympathy whatsoever with any one who evades income-tax or sales-tax or any other taxes and indulges in malpractices. Well, the greatest punishment should be given to that man or that company whoever it may be. But, I would request the Government that for Heaven's sake, do not punish the man who is seriously and honestly interested in increasing the production of the country which is in the overall interest of the nation. On the other hand, that company or that man who increases production should be amply rewarded not by giving warnings or stern action but by calling him a 'good worker' and a 'patriot'. Because, Sir, he brings Socialism quicker to the country.

Now, Sir, I will speak something about the 1956 Industrial Policy Resolution. For all practical purposes, it is out-dated. It should be further re-oriented in the present context, so that the private sector is fully allowed to be associated with the Government in creating a massive industrial development. And, Government should not always think that the people in the private sector are bad people, and they should not be treated with suspicion and doubts.

Now, Sir, I wish to speak something about the small-scale sector. All the sectors-whether it is big or small, whether it is public or private —are all one 'national sector' as our Prime Minister Madam Indira Gandhi has said in the Rajya Sabha a few days back. But, I wish to say, this, that the small-scale sector needs a special consideration by the Government because it has not got the resources at its command. May I therefore suggest to the Government that they should be more sincere in this respect and encourage and give all help and facilities and loans to them ?

Regarding the public sector I would not like to say anything more except that it is not going to function properly until and unless its full installed capacity is fully utilised. In today's Time of India, there is an item stating that 50% is the idle capacity in the Heavy Industry. How? I do not understand how this public sector is going to work and make money if its installed capacity is utilised only to the extent of 30% or 40%. The same thing applies to the private sector. It is the duty of the Government to supply necessary raw materials and necessary power supply and other facilities and to see to it that every unit in the public sector or private sector or any other sector is working to its installed capacity. As a matter of fact, I have a desire that the units should work more than their installed capacity. And, the Government should compliment that unit. But, what I find is that the Government of India seems to be somewhat allergic in this respect. I do not know why if anybody or any unit increases production more than the installed capacity they think of taking some action against them. I do not like that. That is one thing which I would like to say.

Then, I wish to say something about the public sector. In Khetri, in my constituency, there is a copper project and a fertilizer project also. I think it is going to cost over Rs. 100 crores. I have been telling the Petroleum Ministry, the Ministry of Industrial Development and every other Ministry : for Heaven's sake connect these with a Railway line; otherwise this project is going to be a failure. But, Sir, my voice as it seems, is just a cry in the wilderness. I have got a letter from the Railway Minister saying that the Railway is not thinking of connecting this unit with any railway siding.

How are they going to get the raw materials? It is going to be very uneconomical on account of not having a rail-line connection. With my experience in business and industry I can say that this project is going to be a failure if the Government of India is not going to connect this project with a railway line.

I want to speak something about the delay. I shall just read a news item which has appeared in the *Financial Express* of the 20th January. This Ministry has clarified a point after nine years. It says :

> "The Union Ministry of Industrial Development has issued almost after nine years a clarification regarding the policy on grant of lease of Government land to somebody regarding salt manufacturing."

Nine year's time is a very long period. I hope the Government will take note of this.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Thank God this has not taken ten years.

SHRI R. K. BIRLA : If the hon. Minister and his associates are very busy in other important work and they cannot attend to the

disposal of the files, I would suggest that they adopt a method called "Gajrajsinghji's method". Shri Gajrajsinghji was the Prime Minister of a Princely State when Britishers used to rule us. The Viceroy and the Governor-General's post was occupied by one person at that time. He went to see that State. The Secretary was an I. C. S. Officer. He told the Prime Minister Shri Gajraj Singh that the *bara lat sahib* was going to come here and the public was going to give him a reception. He told him: "They are going to tell him that the files have been acumulated and that you have not been able to dispose of those files." To this Shri Gajraj Singh said that he should not bother about it and that he knew of his ability as the Prime Minister of that big State to dispose of the files before the *bara lat sahib* reached that place. One day before that, the files were brought before Shri Gajraj Singh. He said : 'put 50% of the files on the right side of the table and the other 50% on the left side of the table.' Right side is accepted while the left side is rejected. I say that even if this policy is accepted by this Government, the disposal of the files will be very quick.

Thank you very much.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Since I am leaving for Kanpur, let my name be called.

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : अध्यक्ष जी, देश का आर्थिक चित्र बनाने में उद्योग-धंधों का बहुत बड़ा हाथ होता है। पिछले बीस सालों में हमारे देश में इस दिशा में जो तरक्की हुई है या जो होनी चाहिए तथा हमारे देश में मिक्स्ड एकोनामी के आधार पर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों में, हमारे देश के आर्थिक चित्र की उन्नति के लिए और देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत करने के लिए जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनके सम्बन्ध में मैं दो एक सुझाव अवश्य देना चाहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी जो समाजवाद की कल्पना है, जिसके आधार पर हम अपने देश का आर्थिक चित्र बनाना चाहते हैं, उसमें पूरी तरह से विश्वास करने वाले हमारे मंत्री महोदय हैं परन्तु मैं समझता हूँ कि बहुत सारी खामियों की जानकारी उनको नहीं हो पाती है। जैसे कि मैं आपको बतलाऊं कि आप जो उद्योग-धंधों की कमेटीज बनाते हैं जैसे कि फेडरेशन है है उसमें जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बीस तीस उन्हीं की शिरकत हो पाती जो छोटे उद्योगपति है, दस बीस लाख रूपए के उद्योगवाले उनकी शिरकत उन कमेटीज में नहीं हो पाती है। मै समझता हूँ कि आपको उन कमेटीज में छोटे उद्योगपतियों को भी रखना चाहिए।

इसी प्रकार से मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक सीमेंट के प्रोडक्शन का सवाल है, हमारे उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। दक्षिण भारत में भी है लेकिन इस तरफ ज्यादा होता है। अब जहाँ तक सीमेंट की प्राइस का सम्बन्ध है, उसमें समानता नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी आपको लिखा है और पुनः कहना चाहता हूँ कि सीमेंन्ट की प्राइस के सम्बन्ध में कोई समानता होनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि मार्केट में सीमेंट अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचनी चाहिए। आपने 14 अप्रैल, 1969 को इस बात की घोषणा भी की थी कि सीमेंट को डी--कंट्रोल करेंगे लेकिन फिर अचानक आपने 20 दिसम्बर 1969 को कह दिया कि अभी हमने इसको कुछ दिनों के लिए स्थागित कर दिया है। मैं समझता हूँ कि सीमेंन्ट को डी-कन्ट्रोल करना चाहिए। यह सही है कि गरीबों तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, यह सही है कि निम्न स्तरीय व्यक्तियों तक सीमेंट पहुंचे, इस बात को आप देखें लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है वह अधिक मात्रा में मिलों में ही न पड़ा रहे क्योंकि फिर उसका असर उसके प्रोडक्शन पर पड़ता है, मजदूरों पर पड़ता है। मैं समझता हूं सीमेंट डी-कन्ट्रोल होने और अधिक से अधिक सीमेंट बाजार में आने से सभी लोगों को वह उपलब्ध हो सकेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सीमेंट को डी-कन्ट्रोल करें।

[श्री सीताराम केसरी]

चौथी बात यह है जिसको आपने खुद माना है कि जो हमारी टेक्सटाइल को इन्डस्ट्री है वह बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत सारा माल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होता है बल्कि हमारे देश की बहुत कुछ आर्थिक बुनियाद इस इन्डस्ट्री के ऊपर आधारित है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ आपका विशेष ध्यान जाना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री के द्वारा हम जितना एक्सपोर्ट करते थे उसको देखते हुए आज एक हमसे छोटा मुल्क हमारे कम्पटीशन में आ गया है।

पाँचवीं बात यह है कि आज हमारी पब्लिक सेक्टर की इन्डस्ट्रीज हैं जिनमें कि हमको हानि होती है, मैं समझता हूं पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बनाया जाय उसमें ऐसे लोगों का समावेश होना चाहिए जिनको कि पब्लिक सेक्टर के प्रति विश्वास की भावना हो, जिनको कि पब्लिक सेक्टर में फेथ हो। जब तक उनमें फेथ नहीं होगी तब तक उनके काम में वह एफीशिएन्सी नहीं आएगी। विश्वास के आधार पर ही काम करने की स्पिरिट पैदा होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर में जो लास हो रहा है उसको रोकने के लिए और पब्लिक सेक्टर जो कि हमारे समाजवाद की आधार शिला है, इस सरकार की जो घोषित नीति है कि समाजवाद के आधार पर हमारे देश का आर्थिक चित्र बने तो इसको सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में या उसके संचालन में उन लोगों को रखा जाये जिनको समाजवाद में विश्वास हो ताकि पब्लिक सेक्टर को चलाने में उनको ताकत मिले।

जहां तक लाइसेन्स देने की बात है, आपने स्वयं ही कुछ छूट दी है जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि वह कुछ छोटे-छोटे उद्योगपतियों के नाम पर लाइसेन्स ले लेते हैं। इस प्रकार की बात हमारे देश में चल रही है। इस लिए आप इस बात की विशेष निगरानी रखें ताकि छोटे छोटे उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहन मिल सके। विदेशों में बहुत सारे इंडस्ट्रीयलिस्ट्स इस बात को कहते हैं कि भारत में इंडस्ट्रीज में तरक्की के लिए बहुत सारे अवरोध हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह गलत बात है। इंग्लैंड, अमरीका इत्यादि में जो तरक्की होती है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीयलिस्ट्स हैं वे किसी एक चीज में स्पेशलाइज करते है जैसे कि मोटर बनानी है तो उस में स्पेशलाइज कर लिया। इसी तरह से ट्रैक्टर की इंडस्ट्री एक तरफ है। यह नहीं होता है कि ट्रैक्टर का इंडस्ट्रियलिस्ट सीमेंट का उद्योग भी चलाए, चीनी का उद्योग भी चलाए और वेजिटेबिल घी का भी उद्योग चलाए। इस तरह की चीजों पर आप को नियन्त्रण करना होगा ताकि बहुत सारे जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वह भी उस जगह पर पहुँच सकें। अन्यथा हमारे यहां पर जो एक्युमुलेशन आफ वेल्थ होता जा रहा है उसका सब से बड़ा कारण यही है क्योंकि एक उद्योगपति दस तरह के काम करता है और दस नामों से करता है। इस लिए मैं आप से कहूँगा कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ही काम करने के लिए दीजिए तभी इस देश का फायदा होगा और जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप के द्वारा जो लोन दिया जाता है, उसका जो तरीका है उससे जो छोटे उद्योगपति है—मेरा मतलब बड़े पूँजीपतियों से नहीं है—जो छोटे उद्योग धंधे करने वाले है उन तक आप की मदद नहीं पहुँच पाती है।

मैं समझता हूं कि इस दिशा में आपको एक कदम रखना चाहिये ताकि उन लोगों तक मदद पहुंच सके। मैंने जैसा कहा छोटे छोटे उद्योगपति सारे देश में फैले हुए हैं, उनकी आपके यहां कोई सुनवाई नहीं है, कोई से नहीं है। वह लोग फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कौमर्स के मार्फत ही आ पाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको

उनका हित फेडरेशन से उनको अलग रख कर देखना चाहिये तभी आप समझ सकेंगे कि इस देश में और भी छोटे छोटे उद्योगपति हैं। ऐसे उद्योगपतियों को आपको डायरेक्ट कमेटी में रखना चाहिये, न कि फेडरेशन के मारफत।

जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का उसका मेरे ख्याल से सभी में वितरण होना चाहिए अभी होता क्या है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट का एक प्रोडक्शन हो गया उस पर उसी का आधिपत्य हो जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि सभी जगह वह उत्पादन नहीं पहुंच पाता है।

मैं मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी कम्पनियों द्वारा डोनेशन देना बन्द कर दिया जिससे देश की संस्थाओं को आपने बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। इससे जो मोनोपली की भावना केन्द्रित होती थी, और जो पूंजीपतियों के द्वारा इकट्ठा धन जाता था जिसका काफी दुरुपयोग पूंजीपतियों द्वारा किया जाता था, वह अब नहीं हो सकेगा। इस प्रवृत्ति पर आपने अंकुश लगा कर बहुत अच्छा काम किया है।

एकुम्युलेशन आफ वेल्थ को रोकने के लिए कुछ इस तरह की तैयारी कीजिये, जैसे अमरीका में है। वहां यह तरीका है कि सरकार का जो रेवेन्यू है उसका एक परसेंटेज होता है कि इतने परसेंटेज से ज्यादा किसी के पास वेल्थ नहीं होगी, वह कनफिसकेट हो जायगी। मान लीजिये पांच करोड़ का हमारा रेवेन्यू है, अब अगर किसी इंडिविजुअल की राष्ट्रीय आय से एक परसेंट ज्यादा वेल्थ होती है तो वह कनफिसकेट कर ली जायगी। इस प्रकार से मोनोपली आफ वेल्थ पर अंकुश लग सकता है।

हमारे मंत्री महोदय ने बम्बई कांग्रेस का जो प्रस्ताव है, और जो समाजवाद की परिकल्पना है उसकी पूर्ति में बहुत बड़ा कदम उठाया है, उठाते हैं और मैं समझता हूं कि आगे भी उन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर यहां का आर्थिक चित्र, जो समाजवाद के आधार पर बनना है, उसे बनाने में योग देंगे, और इनकी दृष्टि में हमेशा यह बात रहेगी कि हमारे देश का आर्थिक चित्र ऐसा हो कि उद्योग धंधों के द्वारा जो भी उत्पादन हो वह गरीब से गरीब तक पहुंचे जिससे देश के सामान्य नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठे। क्योंकि आज कल के जमाने में बिना उद्योग धन्धों की तरक्की के यह आगे नहीं बढ़ेगा।

अन्त में मुझे एक बात बेकार पड़ी हुई वेल्थ के बारे में कहनी है। आज बहुत सारी वेल्थ लोगों के पास बेकार पड़ी हुई है। मेरा खयाल है कि उसके लिये आपके पास एक इन्सेन्टिव होना चाहिये ताकि वह धन मार्केट में आवे, उस बेकार पड़े हुए धन का इनवेस्टमेंट हो। तभी आपको समाजवाद की स्थापना में सहयोग मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI BABURAO PATEL (Shajapur): This is the Trishul Ministry of our Government. It is a three-pronged trident in the hands of a very powerful and intelligent person. And it is a dangerous trident. The first prong is Industrial Development whereby licences are given to industrialists and expansion is allowed or disallowed to them; the second is Internal Trade where distribution is controlled or prices are prescribed; the third one is Company Affairs where industrialists whether they commit a fault or not are still punished severely and they are thrown out of business if they do not make a profit. Fortunately, this section of the Company Law which punishes private enterprise for not making profits is not applied to the public sector. Otherwise seventy-five per cent of the public sector concerns would have gone out of business. In fact those in charge of public sector projects do not even know how to spell the word 'profit' and that is why they are making 'progress in collecting losses'.

Coming to this Ministry and its dangerous implications in the hands of a very clever man, I want to point out that last year we celebrated the Centenary of Mahatma Gandhi and the Government of India gave a donation of Rs. 1.20 crores. It is well known that Mahatma Gandhi used to sing a prayer : "Raghupati Raghava Raja Ram—Ishwara Allah Tere Nam"

[SHRI BABURAO PATEL]

This prayer could not possibly have been sung by the Muslims of India; Raghupati Raghava cannot be sung by them and their great friend Mr. Fakhruddin Ali Ahmed had to find something for the Muslims in secular India, otherwise the whole year would have been a waste for them. They would not have had anything to celebrate. He, therefore, resurrected the ghost of Ghalib and had the centenary celebrations of Ghalib to compensate Muslims. And for that our Government gave, according to the population ratio of 6 : 1, a donation of Rs. 20 lakhs... (*Interruptions.*)

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order I have great regard for hon. Member Baburao Patel, for his age, intelligence, for his everything. He is speaking on the Demands of Industrial Development and Internal Trade and Company Affairs. I have no grouse against it. He is actually bringing in Ghalib's centenary celebrations. How does it fall within this Ministry ? Raghupathi Raghava, Mirza Ghalib—these are not relevant. Ghalib never wanted a licence.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not a point of order; if at all, the question of relevancy arises, and it is a matter of opinion. Personally I feel that...

SHRI S. M. BANERJEE : If Ghalib had been alive he would have only said, after hearing his speech :

तुझे हम वली समझते, जो न इर्रलेवेंट होता ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It would be good if Members are relevant, but I can only appeal to them.

SHRI BABURAO PATEL : Sir, I shall presently show how it is relevant. Money had to be collected for Ghalib's Centenary. And that money, of all persons, came from industrialists, people like Birlas and Tatas, who spent lakhs of rupees on the Ghalib Centenary. By what stretch of imagination would these people who love the jingle of their money like to spend over romantic poetry? Neither the Birlas, who are my friends, nor the Tatas, who are also my friends, know a word of Urdu or Urdu poetry. Birlas paid a lakh of rupees and Tatas paid Rs. 25,000 for the Ghalib Centenary. This money has come out of them because of a magical combination of words. The safes are opened these days not by the combination of keys but by the combination of words. The safes of the banks, the safes of the industrialists, the safes of the rich are opened by a combination of letters or the combination of words. The six words—Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs. That is a wonderful combination for opening the safes of the industrialists. And this combination of six words opened the safes of Birlas and Tatas. They had nothing to do with Urdu poetry or Ghalib's Centenary. Ghalib's Centenary was conducted under the aegis of the Education Ministry. But those industrialists knew that licences and expansion were in the hands of Shri F. A. Ahmed who was the sponsor of the Ghalib's Centenary. (*Interruption*). You sit down now; afterwards raise your objection.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam) : How can you ask the Hon. Member to sit down ?

SHRI BABURAO PATEL : Now, Sir, this is how the money came. I do not say that Shri F. A. Ahmed did at any stage influence anybody. But he should have been very careful about something worth which his name was associated. He should have been very careful to see that as his name was associated with industrial development, with the industries, with the industrialists and, at the same time, with the Ghalib centenary, he should have taken particular care to see that the industrialists did not pay for this, even if they happened to have a great love for Urdu poetry which they do not have. (*Interruption*) I know it. I have known them.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA : Are you fond of Urdu poetry ?

SHRI BABURAO PATEL : No, I am not. I am all for Tamil poetry and also..(*Interruption*)... for Tyagaraja.

What happened ? After this, I expected that something would be done for the expansion of our motor-car industry, particularly after this payment. Today, in our country, there is an annual demand for 70,000 cars and we are actually manufacturing 35,799 cars per year according to the last year's figures. We are, therefore, short of 35,000 cars every year while we actually have an annual capacity of 140,000 cars to be manufactured in our country developed during the three Plans that we have had.

Now, Sir, Hindustan Motors applied in June, 1965 to expand their production by 80,000 cars. Premier Automobiles applied in May, 1968 to expand their production by 50,000 cars. Both these expansions were refused by the Industries Ministry. Why ? I will tell you. There are two reasons. The first reason is that Government has controlled the sale of cars and compelled the people to deposit Rs. 2,000 per car with the post-offices. This money has now mounted to a sizeable amount of Rs. 13,82,46,000. This money is being used by the Government at three and a half per cent interest per year whereas you cannot get any money at that rate in the market, and the Government is now very reluctant to return this money by allowing the production of car to increase and by letting the people have the cars.

Another thing is the small car project racket. Shri F. A. Ahmed has been talking for the last three years about a small car project. How small is this small car going to be ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Hon. Member's time is up.

SHRI BABURAO PATEL : Is it not very interesting ? Don't you like the story, Sir? The car is small either in price or in size. We have already a small car, the Standard car, where one has to fold oneself to get into the car. As regards the price, one third of the price of a car is taken by the Government by way of either local taxes or Central taxes. If the taxes are reduced, the car automatically becomes cheap, and the Standard car is small enough for all purposes. Then what is the idea of another small car? The small car project was being dangled as a carrot before the public because Sanjay, the son of the Prime Minister, was getting ready with a small car project. When Shri F. A. Ahmed saw the small car and Sanjay wanted him to take a trial ride in it, Shri F. A. Ahmed probably thought it to be a dangerous ride and said : "Let the Prime Minister go first." (*Interruption*) Now that thing is over. Sanjay has failed to build a car. Let us not talk of this small car any more especially when the Planning Commission has not agreed to the project of building a small car in India. We have three cars. All that we want to do now is to allow the production to expand. There is production capacity for 1.40 lakh cars per year. 70,000 cars are needed. We have double the capacity. But Shri Ahmed raises all sorts of objections, says that they should not expand. The same is the story about scooters. Scooters are not being allowed to be manufactured.

Regarding the Asian Cable Corporation, during the last session the Hon. Minister had said that a letter put up by Mr. Kanwar Lal Gupta was considered to be doubtful or forged. Today I have got a report from Simla from the experts saying that the letter signed by Mr. B. D. Kalelkar is not forged and is genuine. According to the document, Mr. B. D. Kalelkar, who is supposed to be the Director General of Technical Development, Mr. N. N. Wanchoo, who is supposed to be the Secretary and Rana K. D. N. Singh, the Joint Secretary all these have conspired to grant more licences than they required to certain firms. There are 14 firms. They have sold the goods in black market and made a lot of money. One fellow called Mr. K. P. Goenka, who is obviously a rich man and who is supposed to be in toe with the Minister himself, is supposed to have made Rs. 50 lakhs for Asian Cables in one deal alone. That is some licence for polyethelene. I hope these allegations are false. But there are rumours in the market. And it is the duty of a good and a nice man like Mr. Fakhruddin Ali Ahmed to investigate them aad not scotch them, because unless he makes a genuine and sincere effort to put down corruption, there is no chance at all of putting the socialism of the Prime Minister into effect. There are 14 firms mentioned here. I do not want to embarrass the firms by mentioning their names. They are all, under CBI investigation and according to the reply given by the Home Minister, involved in one crime, and that is of taking more licences than their requirements and selling the excess in blackmarket. This is a very serious charge. An educated man like Mr. Fakhruddin Ali Ahmed, who is a barrister, should understand that when a charge is made on the floor of the House, when the Home Minister admits that there is something doubtful about it and when the matter has gone to the CBI, it is up to him to say, "I will appoint a committee to go into it". There is no use sitting with his hand on his chin. He must do something. Otherwise, there will be no end to corruption. Then where is the socialism going to come from ?

This is the letter and I would like to put it on the Table of the House.** This is the report. These are the photostat copies. In another copper deal of 500 tons, the Asian Cables are reported to have made Rs. 20 lakhs. If the

** The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

Minister allows people to make money like this, if he allows corruption in his own Ministry, where is this to end ? He could certainly suspend Shri Wanchoo, Shri Kalelkar and Shri Singh and find out what is the truth. On the other hand, there are some good people. But what is their fate ? There is one Shri R. K. Gupta who has been able to trace the culprits. He has been transferred from Delhi. So, honesty has been punished and dishonesty has been rewarded. If things like this happen, then our Prime Minister's socialism will fail. Since you are her right hand man, I am appealing to you personally as a citizen that something must be done in this matter. These people must be suspended and an enquiry must be made. Otherwise, we are all doomed. As it is, a poor country like ours cannot afford the luxury of crime and corruption. If you do something, I will be personally thankful and I will not have to speak against you in future.

One Col. V. P. S. Menon has submitted some important report about the advisability of doing things. This report was completely neglected, completely ignored, because it suited this man, Shri P. D. Kalelkar to do so. He wanted to make Rs. 4 lakhs out of the deal. It is written in that letter, it is in his own handwriting and the handwriting has been found to be genuine and not forged. When an expert has declared that handwriting as genuine, I think it is your solemn duty to look into the matter and make a beginning by suspending these people first. Otherwise, all the documentary evidence will be destroyed. I think it is your duty and I appeal to you as an honorable citizen to do the needful.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I must congratulate the Minister for having to his credit a certain amount of industrial growth in the country, but at the same time I must bring to the notice of this hon. House that even after President's rule there has been no sense of security in West Bengal. Any kind of investment is yet shy. President's rule, Sir, was declared on the 19th March. Even after that gherraos are continuing and industrial climate is full of unrest and small entrepreneurs, who are the life and soul of any economic policy of any country, are continuously harassed. A most heartrending tragedy took place on the 26th of March. One Shri Samarendranath Chatterjee of Dominion Rubber Factory of Calcutta committed suicide with his wife because there was gherrao and demands were made by the workers which were unreasonable and which he could not meet. He was prepared to pay the bouns to a certain point and date but they wanted bonus beyond 31st March. Not only was he threatened with assault but was told that even his wife would be assaulted ! So, leaving behind their seven-year old son, he and his wife committed suicide. The industrial climate of West Bengal is still full of unrest. I would request the hon. Minister that the industrial climate must be normalised and gherraos and strikes must be categorically stopped if any kind of industry is to grow in West Bengal.

Sir, you must give me a little time so that I can give a full picture of West Bengal to the House. It has been stated that 16.6 million man-days were lost in India because of strikes and lockouts out of which Bengal tops the list with 10.2 million mandays. As regards industrial disputes, 392 disputes have been brought to the notice of the tribunals and courts in Bengal whereas 647 disputes have been brought to the notice of the tribunals and courts in Maharashtra. But, in spite of the smaller number of disputes, you can understand how deep, far-reaching and bitter has been the struggle in Bengal which has cost us a loss of 10.2 million mandays. And, if this climate continues, then it will be absolutely impossible for the small entrepreneur to function. Sir, the Prime Minister when she visited Bengal in 1969, said that "the small entrepreneur does not have a bad image in front of the public", because he is using his talent and the small amount of money that he can get from Government and his own resources which are really taking the economy of the country onwards.

My hon. friend opposite has said in a very sweeping statement that big industrialists have supported the Ghalib Centenary celebrations because they wanted to get favours out of Mr. Fakhruddin Ali Ahmed. That is an entirely wrong statement and I disagree with that. There is a saying that: "she who cooks also adorns herself". Because a business-man runs a business—whether big or small—it does not mean that he cannot appreciate poetry, and to insinuate motives into his having supported the Ghalib Centenary, I think, is very uncalled for.

Sir, I would bring to the notice of the hon. Minister that there are two or three small enterprises about which I can give instances and, I think, he must take note of them. There

[SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI]

is the hosiery industry of Bengal. They have asked for a quota of Rs. 3,46,000 worth of needles to be imported, and against this the licence given to them is worth Rs. 86,000, and each machine has to have 24 needles and if the needle is not there the machines lie idle. I think small enterprises like this should be given their full quota so that the industry can go on. They employ over 14, 000 people and, have functioned since 1921 or 1923. Secondly, look at this hand-made iron safe industry. It has never been in the history of taxation that a hand-made industry which comprises twenty, thirty or at the most hundred people in each unit should have Central Excise put on it. It has never been done before. This time they have been saddled with Central Excise of 10% over and above other taxes which they have to pay.

Then I should like to bring to the notice of the Minister that there are the weavers in West Bengal and in India. Cotton yarn should be made available at the same price to weavers who employ thousands of people and are the backbone of employment in a State like Bengal. They do not get the yarn at the same price as in Madras. We must have the cotton yarn at the same viable rate as we have in Madras.

I would also like to bring to the notice of the Minister the performance of the Hindustan Salt Works. The Hindustan Salt Works was asked and here the private distributors cooperated with this public sector entirely and well. West Bengal needed 40,000 tons of salt for Durgapur Project. The Hindustan Salt Works sent only 2,000 tonnes. Why was that? Why could not they send 40,000 tonnes of salt? The distributors were willing to distribute. The Hindustan Salt does not run at a good profit either. But if they cannot fulfil the demand how can that industry run profitably?

Also, funnily enough, now a 20% freight charge is going to be levied for the carrying of salt by coastal shipping. If this 20% freight increase is allowed, then the distributors will not be able to carry salt by coastal shipping, and the Calcutta port will lose at least Rs. 40 lakhs. This extra freight charge must be reconsidered by Government. Salt, Sir, is an everyday necessity for everybody for everything. We cannot exist without salt. So, I hope that these points will be considered by the Minister so that trade and industry in the country gradually gathers momentum. I can do no better than quote Acharya P. C. Ray who always said "The talent and industry of India, is her soul, and it is the small entrepreneur who will ultimately forge the sinews of India's economy."

I earnestly hope that the Minister and the Government by their policies will not kill that soul nor weaken the sinews which will ultimately forge all the sinews of our economy. It is not the big industry that will really help you out; it is the thousands of people who need to be employed all over Bengal and India, the educated unemployed, who can only find their own sphere in small industries, who will carry the economy from strength to strength. The small industries must be looked after so that we do not weaken industrial potential and the entrepreneurs who by their talent and drive will redeem the soul of India from recession and backwardness.

After all, businessmen and small entrepreneurs are out to serve, not always out to make money. They are there to serve the country. Here I would also bring to the notice of the Minister that I agree with my hon. friend that the cement industry should be decontrolled. You can also have the cement industry, with not so much capital, in West Bengal where you can get actually 6 million tonnes of slag from the iron foundries. The Government could assist in putting up the cement industry in West Bengal where there is none. I hope, the Minister will think in these terms and if any entrepreneur comes forward to put up a cement factory, he will get all the help that he needs.

Lastly, I would like to know how much money has been made available from the nationalised banks to the small entrepreneurs who were really supposed to be helped by the nationalisation of banks. I hope, the hon. Minister will make it clear in his reply as to what percentage of loans that have been given have gone to the small entrepreneur so that the small trader and a small businessman may hold his own against the big cartels that are already there . I hope, the cartels and monopolies will be curbed but the big business, if it really serves the country, will not be unduly hampered and the small businessman will be able to go hand in hand with them.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं इस बात की मुजम्मत करना चाहता हूं कि मेरे मुअज्जिज दोस्त, श्री बाबूराव पटेल, ने इस सदन में यह

कहा कि श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद द्वारा ग़ालिब सेनटेनरी मनाने के लिए बिड़ला और टाटा से पैसा लिया गया। यह बात बिल्कुल ग़लत है कि श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद महज इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट मिनिस्टर होने की वजह से ग़ालिब सेनटेनरी कमेटी के चेयरमैन या कानवीनर बनाए गए। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम है कि उनको उर्दू जुबान में दिलचस्पी है और वह मिर्जा ग़ालिब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं—शायद वह मिर्जा ग़ालिब के डायरेक्ट डिसेडेंट हैं। हमें तो इस बात की खुशी थी कि हमारे एक मंत्री ने ग़ालिब सेनटेनरी को मनाने में हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि श्री बाबूराव पटेल को एक लिट्रेरी फ़िगर होते हुए इस बात का ज्ञान होना चाहिए था। बजाये इसके कि वह श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद की तारीफ़ करते या उनको इस बात की बधाई देते कि उन्होंने सिसकती उर्दू जुबान को दोबारा जिन्दा करने की कोशिश की, उन्होंने श्री अहमद को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया।

दूसरी बात मुझे यह बुरी मालूम हुई कि श्री पटेल ने गांधी जी का जिक्र किया। श्री पटेल का खयाल यह मालूम होता है कि गांधीजी ने सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए "रघुपति राघव राजा राम" के आगे "ईश्वर अल्लाह तेरे नाम" जोड़ दिया था। मैं समझता हूं कि जिन लोगों के माथे पर फ़िर्कापरस्ती का निशान चमकता है, उनको हर एक बात में फ़िर्कापरस्ती की बू आती है। वे समझते हैं कि "रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम" गाना कोई गुनाह है। माननीय सदस्य कम से कम अपनी बजुर्गी का खयाल करें, अपने सफेद बालों का खयाल करें, जो शायद तजुर्बे से नहीं, बल्कि धूप से सफेद हुए हैं। वह इस सदन में इस तरह की बातें न कहा करें और अगर वह कहें, तो हम उनको रोकने की कोशिश करें।

मैं कोई लाइसेंसिज का बड़ा हामी नहीं हूं, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि यह नई लाइसेंसिंग पालिसी डिफेक्टिव है कि एक करोड़ रुपये या उससे कम के किसी उद्योग के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। जो लोग एक करोड़ रुपये से ज्यादा का कोई उद्योग चलाना चाहते हैं, जिनके साथ मोनोपली या एकाधिपत्य का शब्द जुड़ा हुआ है, उनके मामले तो किसी कमेटी या कैबिनेट के सामने जायेंगे, लेकिन इस नई पालिसी का नतीजा यह होगा कि कुछ लोग अपने उद्योग को छोटे छोटे उद्योगों में बांट देंगे। मालिक एक होगा, लेकिन नाम दस आदमियों के होंगे और इस तरह मानोपली, एकाधिपत्य, जारी रहेगा। फ़र्क इतना ही होगा कि एक बड़ा उद्योग न होकर कई छोटे छोटे उद्योग होंगे। उदाहरण के लिए आप स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का उद्योग ले लीजिए। कुछ बड़े उद्योगपति छोटे छोटे उद्योग खड़े करके अपना एकाधिपत्य कायम रखेंगे, क्योंकि मालिक वही होंगे और काम करने वाले दूसरे होंगे। यह एक गलत बात होगी।

माननीय सदस्य, श्री बिड़ला, ने मिनिस्ट्री आफ़ फोरेन ट्रेड की डिमांड्ज पर बोलते हुए श्री भगत की बहुत तारीफ़ की थी। आज मैंने उनको सुना नहीं है, लेकिन आज भी उन्होंने कुछ तारीफ़ करने की कोशिश की होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 1956 के इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन के द्वारा देश की अर्थ-व्यवस्था को समाजवाद की तरफ एक नया मोड़ देने की कोशिश की गई थी। उसका उद्देश्य यह था कि देश में एक्युमुलेशन आफ़ वेल्थ न हो, और देश के धन का बंटवारा सही ढंग से हो, ताकि ग़रीब और ग़रीब न हो और अमीर और अमीर न हो।

लेकिन आज देश की हालत क्या है ? जो लोग 1947 से पहले या कुछ बाद लखपति थे, वे करोड़पति हो गये और जो करोड़पति थे, वे अरबपति हो गये। दूसरी तरफ़ जिसकी आमदनी 100 रुपये थी, महंगाई ने उस की कमर तोड़ दी और उसकी आमदनी सिर्फ 50 रुपये रह गई है। जिसकी आमदनी 50 रुपये थी, वह बेकार हो

[श्री स० मो० बनर्जी]

गया है और बेकार एम्पलायमेंट एक्सचेंज के चक्कर लगाकर या तो खुदकशी कर रहा है और या डाका डालने की कोशिश कर रहा है। जो पहले एक छोटे मकान में रहता था, वह अब झोपड़ी में रहता है; जो झोपड़ी में रहता था, वह अब सड़क पर सोता है और सड़क पर सोने वाला बिना कफ़न मरने जा रहा है। फिर भी कहा जाता है कि तरक्की हुई है।

मानोपलीज कमीशन, महालनवीस कमेटी और दत्त कमेटी की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इस मुल्क में मानोपली बढ़ी है, घटी नहीं है। मैं इस सिलसिले में बिड़ला, टाटा और गोयनका बिजिनेस हाउसिज के बारे में आंकड़ों को यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर मानोपली को खतम करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। जब यहां पर बहुत जोरों से मांग की गई, तो सरकार कमीशन बिठाया गया। मुझे मालूम नहीं कि उसने अपना काम शुरू किया है या नहीं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि कुछ और बिजिनेस हाउसिज को इस एनक्वायरी के अन्तर्गत लाया जाये। जैसे कि इस हाउस में बार-बार यह सवाल उठाया गया है, मोदीनगर के मोदी परिवार के खिलाफ़ एनक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सुना गया है कि कांग्रेस के दो हिस्से हो जाने के बाद, सिंडीकेट और इंडीकेट बन जाने के बाद, उस परिवार ने कांग्रेस को काफी पैसा दिया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को साफ़ कर दें।

श्री राम गोपाल शालवाले (चांदनी चौक): किस को पैसा दिया है?

श्री स० मो० बनर्जी : पुरानी कांग्रेस पहले ले चुकी है और नई कांग्रेस अब ले रही है। जो मरी हुई कांग्रेस है, उसकी बात को बाद में उठायेंगे। लेकिन जो कांग्रेस फ़िलहाल जिन्दा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पैसा न ले। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय यह स्पष्टीकरण दें कि मोदी हाउस के खिलाफ़ एनक्वायरी क्यों नहीं की गई है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ सवालात इस पार्लियामेंट में किये गये थे गोयनका हाउस के बारे में। 2 दिसम्बर 1969 को एक सवाल यह पूछा गया था प्रोफेसर हीरेन्द्र मुकर्जी और दूसरे लोगों के द्वारा :

Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the Company Law Department had carried out a detailed inspection of the accounts of a number of companies owned and controlled by Shri Ramanath Goenka following allegations that he and his Companies had diverted funds received from financial institutions and banks for extraneous purposes;

(b) if so, the results thereof; and

(c) whether Government intend to institute a judicial probe into the affairs of the Goenka House?

अहमद साहब ने उस का जवाब यह दिया था :

The Inspecting Officers of the Company Law Board at Calcutta have inspected the books of accounts of the National Co. Ltd., which is controlled by Shri R. N. Goenka, and of the following five other companies which have dealings with it.

पांच कम्पनियों का नाम उन्होंने दिया है और फिर यह कहा है :

The Inspecting Officers have submitted reports on these companies. The nature of action that could appropriately be taken on these inspection reports is under consideration.

उसके बाद क्या हुआ यह मै पूछना चाहता हूँ। मुझे यह मालूम है कि इस कम्पनी ने 30 लाख रुपया स्टेट बैंक से लोन लिया और सिक्योरिटी क्या दी, किस चीज के एवज में लिया? मुझे मालूम हुआ कि गोदाम में जो जूट था उसको दिखा कर यह 30 लाख रुपये लिए गए। लेकिन मालूम यह हुआ कि 30 लाख रुपये स्टेट बैंक से उन्होंने लिए हैं उसकी एवज में 5 लाख रुपये का समान भी वह नहीं है। यह एक अनकवर्ड लोन है। इसके बारे में आगे क्या एन्क्वायरी हुई, क्या हुआ कुछ पता नहीं है।

इसके बाद मैं लाइसेंसिंग के बारे में कहना चाहता हूं।

Grant of Licences to Birlas for setting up Alloy and Special Steel Plants.

यह कहा गया कि बिरला स्पेशल एलाय स्टील प्लान्ट बनाएँगे। उस के बारे में जवाब नहीं दिया। कहा कि अप्लीकेशन उन्होंने दी। लेकिन उसके बाद जो दूसरा सवाल इन्द्रजीत गुप्ता ने किया वह सवाल 16 दिसम्बर 1969 को किया गया, उस में पूछा गया कि :

Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 301 on the 18th November, 1969 and state :

(a) when and where the alloy and special steel plants for which two Birla firms have been licensed, will be established and commence their working;

(b) the present position of the application of the Birlas for setting up one or both these plants as units of M/S Birla Jute Manufacturing Co. Ltd., Calcutta; and

(c) whether the expansion plans of the Alloy Steel Plant at Durgapur have been put into operation ?

आप सोच कर देखिये कि स्पेशल एलाय एन्ड स्टील प्लांट एक हाईली स्पेशलाइज्ड चीज है। वह कौन सेट अप करेगा ? मेसर्स जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता। यानी जूट में क्राइसेस है, यह बार बार बिरला साहब कहते हैं, गोयनका साहब कहते हैं, बजोरिया साहब कहते हैं कि जूट में बड़ी क्राइसेस है। लेकिन क्राइसेस होने के बावजूद भी बजाय इस के कि जूट कारखाने को सही किया जाय, उन को माडर्नाइज किया जाय, उनके लूम अवर्स को ठीक किया जाय, वह करने के बजाय करने क्या जा रहें हैं कि एक तरफ वो जूट कम्पनी का बोर्ड रहेगा, जूट मेंन्युफैक्चरिंग कम्पनी और वह प्रोड्यूस क्या करेंगे ? वह जूट भी प्रोड्यूस करेंगे, जूट बैग भी प्रोड्यूस करेंगे और स्पेशल एलाय भी प्रोड्यूस करेगे। यह आप सोचिए। एक अजीब हालत है कि जो चाहिए सो मिल जायगा। किस तरीके से वहां पर यह काम होगा मेरी समझ में आता नहीं है।

तो उसके जवाब में कहा गया :

An application for transfer of the licences granted to Bihar Alloys to M/S. Birla Jute Manufacturing Co. Ltd. has been received. No final decision has been taken on this application.

A proposal to include a scheme for the expansion of the Alloy Steel Plant, Durgapur in the Fourth Five Year Plan is under consideration.

दुर्गापुर में अभी तक पब्लिक सेक्टर में उस प्लान्ट के बारे में लाइसेंस नहीं दिया गया है, फाइनल परमीशन नहीं दी गई है। केबीना के सामने गया या नहीं गया मुझे मालूम नहीं। लेकिन उस की अप्लीकेशन कोई जूट मेंन्युफैक्चरिंग कम्पनी की आती है, उसका कंसिडेरशन होना न्याय संगत नहीं है।

इसके अलावा मैं कुछ चीजें और कहना चाहता हूँ कि एन्क्वायरी तो हो रही है। यह सही बात है लेकिन अभी जो रयूमर चारों तरफ से बंगाल के अखबारों में निकल रही है, आप उसे पढ़ें, हमारे पास टेलीग्राम्स आते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिरला अपना हेड आफिस शिफ्ट कर रहे हैं यह कह कर कि जहां पर काम मिले, जहां कारखाना चले वहां शिफ्ट कर रहें हैं। मेरे दोस्त ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि कुछ कागजात जो तहकीकात के सिलसिले में जरूरी हैं जो इस कमीशन के सामने जाने वाले हैं वह तो इस नाम पर वह नहीं हटा रहे हैं और यह सही बात है कि चार पांच या सात सौ आदमी कलकत्ते में बेकार हो रहे हैं, तो कलकत्ते से यह कह कर दफ्तर हटाना कि हम प्लेस आफ वर्क जहां हैं वहां ले जाना चाहते हैं अपने दफ्तरों को, इसमें क्या राज है ? मुझे खुशी है कि अहमद साहब ने इसके बारे में लिखा है कि वह इसकी जांच कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह दफ्तर जो हटाये जा रहे हैं उसके पीछे क्या राज़ है।

श्री रामगोपाल शालवाले : इस लिए कि आप वहां लूट मार कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कलकत्ते में सरे आम घूमिए आप का एक शाल लूटा नहीं जाएगा।

मैं आप के मार्फत दो तीन चीजें और कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो एन्क्वायरी होने वाली है उसको जल्दी किया जाय। उस के बाद में मोनोपली आफ फिलिप्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सारी लाइनें आज फिलिप्स के हाथ में है और एक मौअज्जिज अफसर जो हैं, काफी बड़े अफसर इस मिनिस्ट्री के, वह सुना यह गया है कि फिलिप्स के पे-रोल में है। मैं उन का नाम मंत्री महोदय को खुफिया तरीके से देने को तैयार हूँ। जाहिरा तौर पर यहाँ बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन जो और कोई फिलिप्स के टकराव में आते हैं वह फिलिप्स से टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एक विदेशी कम्पनी को इतना सहारा न दिया जाय कि दूसरे बिल्कुल उसके मुकाबिले में टूट जाये।

दूसरी चीज सकसेरिया मिल के बारे में कहना चाहता हूँ। सकसेरिया मिल बन्द पड़ी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि वह उस को चलाने के लिए तैयार हैं। मामूली अमेंडमेंट होने वाला है। चार हजार वर्कर्स आज तबाही के रास्ते पर हैं। तो क्या फैसला इसके बारे में मंत्री महोदय ने लिया वह बताएं। मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कूपर एलेन को लेकर एक नई जिन्दगी आप वहां लाए हैं, मजदूरों के सामने एक भरोसा हुआ है, एक आशा की लहर दौड़ी है, उनका दिमाग कम से कम उस तरफ जो झुक गया था, पहले जो एक मायूसी उन पर छा गई थी, वह दूर हुई है, तो उसी तरह से सकसेरिया मिल को लेकर उसको चलाने की भी कोशिश करें। हम उस में आप की मदद करेंगे। ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के बारे में जो फैसला हुआ है जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, मैंने उस को पढ़ा नहीं है, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उसके बारे में ऐक्शन वह लेंगे? उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को बदलना चाहिए। चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, हमें बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसे बदला जाय। अगर ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को सरकार लेना चाहती है तो 38 परसेंट शेयर उन के हैं, उस को वह नेशनलाइज करे और नेशनलाइज नहीं कर सकते तो कम से कम बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को बदला जाय।

समाचार भारती और पी टी आई के बारे में काफी कुछ कहा गया। समाचार भारती ने तमाम रूल्स ऐंड रेगुलेशंस का वायलेशन किया है, यह बताया गया। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक ऐक्शन नहीं लिया गया। मैं चाहूंगा कि फौरन ऐक्शन समाचार भारती के खिलाफ लिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि मोनोपली के बारे में आप कुछ करें। मोनोपली की हालत यह है, आप देखें, इतना सब कुछ करने के बाद भी वह किसी तरीके से बढ़ रही है,

Monopoly is increasing by leaps and bounds. If you look down you are baffled; if you look up, you are dazzled; if you look around you are puzzled. That is how monopoly is increasing.

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम आप की मदद करेंगे लेकिन देश में राष्ट्रीयकरण की भावना आप लाइए और मोनोपली को खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मोनोपली खत्म करना चाहेंगे, उसमें सरमायादार जितनी मुखालिफत आप की करेंगे, सिंडीकेट, जनसंघ और स्वतंत्र मिलकर, उनकी मुखालिफत हम आप के साथ मिल कर करेंगे।

SHRI Y. A. PRASAD (Machilipatnam): The Minister of Industrial Development holds an extremely difficult and vast portfolio. He is responsible for the bulk of economic activity in this country. Commendable though the

[SHRI Y. A. PRASAD]

achievements have been on the industrial front in the last 2 years, there are some disturbing signs in our economy which give rise to grave doubts about the rate of growth in the future. There is an urgent need for expansion in several branches of industry to meet the requirements of rising incomes and population. Industrialists are aware of this position but their response has been poor. The new company flotations are few and far between. Consents given for the issue of capital by the private sector companies in 1969, excluding bonus shares were only Rs. 102 crores, as against Rs. 339 crores in 1966. In terms of investments actually made, the showing was pretty worse. In the first six months of 1969, the private sector raised by way of equity capital, preference shares and debentures only Rs. 22.3 crores, as against Rs. 39.5 crores in the same period of 1968. The major part of these issues was by the existing companies and that too in the form of debentures and not risk capital. When the figures for the whole of 1969 are available, the total of capital raised may well fall far short of what it was even in the recession years 1966 and 1967.

Unfortunately, too much time is being spent on deciding who is to establish which industry. There is too much preoccupation with ideology. It is high time the Government made up its mind in regard to the licensing of key industries and acted quickly, without any further loss of time. How long does the Government propose to take to decide about the Mithapur fertiliser project, about the expansion of automobile industry, the setting up of additional steel plants in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, about licensing increase in the capacity of aluminium industry and about establishing pulp and paper factories?

A massive unemployment explosion is on the way. Every year about one million students are coming out of our colleges. About 15,000 degree holders and 24,000 diploma holders in higher technical education are emerging from our engineering and technological institutes. Jobs have to be found for them. Failure to do so will result in a revolution which will destroy our young democracy. How are we going to provide jobs for all these educated young men and women, if two to three years are taken to decide whether an industrial licence is to be issued or not? Let us be honest enough to face the fact that, as of to-day, the public sector has too much on its hands. Look at the eggregious delay in the implementation of vital projects pertaining to non-ferrous metals, aluminium, paper and pulp and Bokaro Steel. Look at the underutilisation of capacity in Durgapur and Rourkela steel projects. Consider the colossal losses in a number of public sector projects, heavy and light alike. Surely, it is high time effective measures were taken to make our public sector projects more efficient and profitable. Otherwise, people will lose faith in us and in our social and economic philosophy.

In saying all this, I am not opposed to the fundamentals of our economic and social policies. What I am opposed to is inefficiency, indecision and ineptitude. All these qualities are the enemies of socialism and, in an underdeveloped country like India, they are the allies of undemocratic forces. Socialism cannot be sustained by mere slogans, however pleasing they may be to the ears of the have-nots. What will sustain socialism is more production and yet more production of the goods that the masses need. That requires hard work and pragmatism in policy-making and execution.

The government has wisely decided that the big industrial houses should not be prevented from employing their talents in the more difficult and capital intensive industries. I want active steps to be taken for implementing this decision. Now that the monopoly legislation has been enacted and a new watch dog has been appointed to keep an eye on pricing and productivity in the private sector, we need not be unduly alarmed at the prospect of these big industrial houses growing still bigger. At the same time, it is true that there should not be excessive concentration of economic power. One solution to this problem is to induce the big industrial houses to pass on some of the traditional and not so difficult industries like sugar, cotton textiles, bicycle manufacture and sewing machines, to mention a few, to other hands as, for instance, medium-sized and small industrialists and cooperatives. Their shareholding in these industries may be offered to the public, so that their ownership may be more broadbased. Further, this will also provide the big industrialists with some liquid resources of their own for investment in the new projects in the core sector.

Everyone is talking of the need for encouraging the emergence of new entrepreneurs and for providing more opportunities for the small and medium sized entrepreneurs. But

this cannot be brought about in isolation. Just as the expansion of the public sector has helped the growth of the private sector, so also the growth of big industrialists will provide greater opportunities for the small and medium-sized industrialists. That way the gap between the big and medium entrepreneurs can also be narrowed. For instance, if production of aluminium which is now in short supply is increased by allowing the existing big industrial houses either to expand their capacity or to establish new units, enough metal will be available for processing into end products by the medium and small industrialists.

The manner in which small industries have been brought into being needs careful examination. There industries will be a greater success and more economical, if they function as ancillary and auxiliary industries linked to mass production of consumer durables, instead of themselves producing the final product on a small scale.

It is high time the Government stopped playing with the small car project, as though it were a toy to please the socialist rajas. The best thing to do will be to let the existing manufacturers to expand their production and thereby become economically viable, with the public sector concentrating on the production of special quality steels so very necessary for increasing the output of vehicles. Automobiles and roads are vitally necessary for bringing about a quick increase in the employment potential and for modernising the economy.

Something must be done to activate the building industry in the private sector, as this is another source of massive employment. House-building is the surest way of reducing economic inequalities and promoting contentment among the people. Think of the immense employment that building industry can offer to the unskilled and skilled workers alike. It is a dynamic catalyst to any economy, more so to ours which has all the potentials required for building houses for the well-to-do as well as the not so-well-to-do. I know roads and houses are State subjects. But the Centre can egg them on to proceed in the right direction through a slight reorientation of the policies pertaining to allocation of resources. But a basic requirement for encouraging building industry is a reducion in the wealth tax on buildings and a higher exemption limit for residential buildings.

There is plenty of scope for import substitution in defence industries. This country need not be so pathetically dependent on Russia and other countries as it is today for its defence equipment, if only it associates the talented industrial houses in the private sector with the manufacture of such equipment. If this is done, a lot of bright young Indians who are working in strategic industries in Europe and America can be induced to return to this country and give their contribution to make this country self-reliant in defence materials.

Finally, a few words about my State, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is far behind others in industrialisation. Out of a population of nearly 40 million, only about 260,000 or 0.62% of total population, are factory workers. Almost all organised industries are concentrated in and around Hyderabad. This is a very unsatisfactory state of affairs. Something positive must be done to establish industries in Rayalaseema and the Coastal districts. The dry area of Rayalaseema would be immensely helped, if a nuclear power station were established there. The coastal districts are ideal for the spread of agro-industries, including food products. Suitable incentives should be extended to the entrepreneurs willing to establish industries in these areas.

With these words, I support the demands for grants under the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.

*SHRI KAMALANATHAN (Krishnagiri): Mr. Deputy Speaker, Sir, before I express my views on the demands for grants of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam, I would like to reiterate the issues raised by our Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Kalaignar Karunanidhi, in the recent meeting of the National Development Council. He had stressed the point that the Constitution of India should be amended in view of the fact that different political parties are in power in the Centre and in the States. I have referred to the necessity of amending the Constitution, as emphasised upon by our Chief Minister, because the situation today is that if a State Government wants to start an industry or if it wants to import raw materials required for starting an industry, it has to go on bended knees before the Central Govern-

*The original speech was delivered in Tamil.

[SHRI KAMALANATHAN]

ment for getting the necessary licence.

Though many worthwhile schemes have been forwarded to the Central Government by our State Government, I have to state that all of them have been administered sleeping pills and put in the cold storage.

If a question is asked whether the Central Government have issued any industrial licence to the State Government of Tamil Nadu after the DMK Party assumed office, the answer would definitely be in the negative. I am prepared to substantiate this statement with statistics. M/s. Phillips India Ltd., of Bombay had submitted their proposal for setting up an industrial unit in Tamil Nadu with an investment of Rs. 191 lakhs to manufacture annually 20 lakh pieces of Integrated Circuits and Semi-Conductor Devices. They wanted to collaborate with M/s. Phillips of Holand for establishing this unit. I need not say much about this particular organisation, as they are world-renowned manufacturers of electronic equipment and their products are always in demand throughout the world. I do not see any reason why we should not avail ourselves of the benefits of their talents in the manufacture of highly sophisticated equipment. I cannot also appreciate the delay on the part of the Central Government in sanctioning this scheme. Our late lamented leader, Anna, as also the present Chief Minister, requested the Central Government time and again to issue sanction for this unit. I request that the Government should expedite the issue of approval for the establishment of this unit.

The Central Government had decided to set up a Marine Diesel Engine manufacturing factory at Ennore near Madras, The former Minister of Defence, Shri V. K. Krishna Menon visited the project-site selected for this purpose and expressed his satisfaction on the proposed site. I am sorry to state that this project has not yet seen the light of the day and no action has been initiated in the matter of setting up this unit even though it had been approved long ago.

The representatives of the Bharat Electronics Ltd., of Bangalore visited Tamil Nadu with a view to setting up a second Electronics Unit there. They selected a site at Ambathur near Madras for this purpose. The Tamil Nadu Government readily offered to place at their disposal the required stretch of land and also assured them of all amenities for the workers. I do not know at what stage this porposal stands now. I would request the Minister to look into this. In the Project Report it had been stated that this project, when implemented, would provide jobs to about 600 unemployed engineering graduates. I would like to point out that through this project you would be able to utilise the services of the engineering personnel and skilled technicians available in plenty in our State.

The National Industrial Development Corporation (NIDC) some years ago sent a team of engineers to Tamil Nadu to find out suitable locations for the establishment of units to manufacture Axle Tubes for Automobiles, Seamless Pipes and Cylinders for domestic and industrial gases. While we have not since heard anything further in this matter; we are hearing that the NIDC is likely to be wound up. Before the NIDC is actually wound up, I request that the projects proposed by the team of engineers of NIDC should be implemented.

In 1968 the Bharat Steel Tubes Company submitted a proposal to the Central Government for setting up a Seamless Steel Tube Plant in Tamil Nadu. The then State Government had also recommended this proposal. But the Central Government advised that this Plant could as well be established in the Public Sector rather than in the Private Sector. Accordingly, the State Industrial Development Corporation prepared a plan in collaboration with the Bharat Heavy Electricals at Tiruchirappalli, which is a Central Government undertaking, and submitted it to the Central Government. It is indeed surprising that the Central Government at whose instance the plan was prepared by the State Government, have themselves not cared to take any constructive step to establish this unit in the Public Sector. The Chief Minister of Tamil Nadu and the State Minister of Industries have repeatedly brought this matter to the notice of the Prime Minister and the Minister concerned at the Centre. But nothing concrete has so far emanated from here. The Tamil Nadu Industrial Development Corporation had also sent their application for establishing a unit to manufacture tyres and tubes for automobiles. This is also pending consideration of the Central Government.

A large number of cases have been brought to the notice of the Central Government that many industrial units are working far in excess of the licensed capacity in violation of the regulations; inspite of hundreds of such com-

plaints no action has been taken by the Central Government in this regard. At the same time, M/s. Eswaran & Sons Engineering Private Ltd., of our State have an installed capacity to produce annually 10,000 tonnes of electrical stampings. But they have been permitted to manufacture only 2,000 tonnes. I take this opportunity to appeal to the hon. Minister that this firm should be permitted to utilise fully their installed capacity; now lying idle.

In 1963, a licence was issued to Madras Alloy & Stainless Steel Ltd., in our State to manufacture stainless steel sheets with an investment of Rs. 10 crores. Unfortunately, the Chief Promoter expired before the scheme materialised. The Tamil Nadu State Government desired to take it up in their own hands, and the State Industrial Development Corporation acquired 51% of the shares of this company. They wanted to establish this Unit in collaboration with I. H. I. of Japan and submitted their proposal to the Central Government. The validity of the licence expired on 31. 12. 1969. I request the Government to extend the validity period of this licence by two years. I also humbly request that permission to start a machine tool plant in collaboration with a Japanese firm may be given at an early date.

I have made specific references to these products because I fear that the Ministers are dissipating their energies in different directions. I make bold to say that if the Government wish to survive till 1972 these projects should be permitted to be established in Tamil Nadu. After being robbed of his self-respect at Rabat, Shri Fakhruddin Ali Ahmed was devoting most of his time in finding answers to the questions raised on the floor of this House about his role at the Rabat Conference. I request him to pay more attention to the problems of Industrial Development in the country. After the split in the Congress Party, Shri Raghunatha Reddy is engaged in enrolling more members for his party. He should spare some time for his official duties and attend to this Departmental work. The universally loved Deputy Minister Shri Bhanu Prakash Singh is enthusiastically hunting for signatures to safeguard the Privy Purses and the privileges of the Princes. I request that all the three Ministers should pay undivided and adequate attention to the Industrial progress of the country.

Sir, with these words I conclude.

SHRI P. K. GHOSH (Ranchi) : The Industrial Policy Resolution of 1956 states:

"The State has been following a policy of supporting cottage and village and small-scale industries by restricting the volume of production in the large-scale sector, by differential taxation or by direct subsidies. While such measures will continue to be taken whenever necessary, the aim of the State policy will be to ensure that the decentralised sector acquires efficiency and vitality to be self-supporting and its development is integrated with that of the large-scale industry."

Thus this Resolution clearly indicates that the Government shall make every effort to help the small-scale industry grow and help that sector financially and also by differential taxation. It is very unfortunate that the major portion of the money that has been invested through financial institutions has gone to the large-scale sector. Not only that. Till the banks were nationalised, 90 per cent or more of the banks' outlay had been in the large scale sector. Small people got very little from the banks. Small industries could not get any finance whatsoever from the banks. In spite of this, though the small industries in our country have not gone to the extent that we should have expected, they have grown and the small-scale industrial sector is today producing, I think, 50 per cent of the value of the materials that are produced in this country. Not only that. The small-scale industries are employing 50 per cent of the men employed in the industrial sector. 50 per cent of the employees in the industrial sector are in the small-scale sector. But the outlay in the small-scale sector is very little; Government's assistance is very little; bank assistance is very little. Therefore, in order to encourage the small-scale industries, we have to change our policies and see that the small-scale industries get more of finances and more of raw materials.

We have brought this new industrial licensing policy. I welcome this policy whereby the licensing limit has been raised from Rs. 25 lakhs to Rs. 1 crore. This will of course help more middle-class entrepreneurs to come up to establish industries without any hindrance. But we have also to look to the danger of these industries comipg into the sectors where small entrpreneurs are working. They may come in competition with the small-scale industries. Therefore, it is very important that we should enlarge the list of items kept for the small-scale industry. Government has also enlarged

the list of these items, but I feel that more items should be reserved for the small-scale industries. I have prepared a list and it is a long list. I want to lay* it on the Table of the House.

15.43 hrs.

(SHRI SHRI CHAND GOYAL *in the Chair*)

Moreover, this new industrial licensing policy raising the limit to Rs. 1 crore will help the large-scale industries to bifurcate their production. What they will do is this. The large units will split up into a large number of smaller units and thereby they would take advantage of the new concessions in the new licensing policy. For instance, one man wants to manufacture a scooter: a scooter factory needs a huge amount of investment; but they can start a scooter factory: somebody will start one unit for manufacturing the engine; another unit will manufacture the frame; and a third unit will manufacture the tyres. Like that, different components will be manufactured in different units. It may be that one big man is interested in the whole thing. He will have a number of small units under different names and thereby manufacture the entire scooter; and he will form another company for assembling the components. Thereby, the whole policy of licensing will be defeated. Therefore, we must have certain measures—the Minister will understand it better—to see that these big people do not take advantage of the relaxation that has been granted in this newly introduced licensing policy.

We have to safeguard the interests of the small industries against competition from large-scale industries because that is not a fair competition. The small-scale industries have less of capital, they do not get raw materials at competitive rates and their cost of production is more. So, they cannot compete with the large-scale industries.

I have already submitted a list of items the production of which should be the exclusive privilege of the small-scale sector. Coming to tax differentiation, I would say that some concession is shown in the matter of excise duty to the small-scale industries, but that is mostly confined to handicrafts and khadi and village industries and not to those small industries which work with power or small machines. I would suggest that all small-scale industries with a turnover of less than Rs. 5 lakhs should be exempted from the payment of excise duty so that they can effectively compete with the large-scale industries.

In the United States and Japan, there is legislation for safeguarding the interests of the small-scale industries. In America there is an Act called Small Business Administration Act. Under that Act, the interests of the ancillaries to the large-scale industries in the matter of cost of production are safeguarded so that the large-scale industries cannot exploit the ancillaries. The administration of the small-scale industries comes directly under the control of the President of USA. There is a list of articles which are exclusively reserved for the small-scale industries, and that list is much bigger than the list that I have propared. In America even the more sophisticated items like the components required for the spacecrafts are reserved for the small-scale sector.

Likewise, in Japan there is the Small and Medium Enterprises Act which regulates the supply of raw materials and pretects the price. I would request our Industries Minister to come forward with a Bill on similar lines to protect our small scale industries.

One of the ways in which the small-scale industries could be helped is in the matter of finance. In the case of financial institutions there are so many formalities which the small-scale industries have to perform and very often they find it difficult to meet with those requirements. They are driven from pillar to post and ultimately they get frustrated and give up the pursuit. Arrangements should be made to ensure that the small-scale industries get finance without much difficulty. If possible, 50 per cent of the outlay of the financial institutions should be earmarked for the small-scale sector, leaving only 50 per cent for the large-scale industries. Otherwise, large-scale sector will influence the financial institutions and will see to it that a lion's share of the credit is given to that sector.

When the banks were nationalised it was stated that it will help the small-scale industries to a great extent. But we find that the position has not improved in any way. The big people are influencing the bank managers and they are getting all the credit. So, I would suggest that in this case also 30 per cent of the outlay should be earmarked for the small scale sector.

*The Speaker subsequently having not accorded the necessary permission, the paper was not treated as laid on the Table.

[SHRI P. K. GHOSH]

Coming to raw materials, 54 per cent of the imported and scarce raw materials are taken away by the large-scale sector, leaving only 6 per cent to the small-scale sector. I would submit that 50 per cent of the scarce and imported raw materials should be reserved exclusively for the small-scale sector.

SHRI VISWANATHA MENON (Ernakulam): This is a very important Ministry and it is responsible for all the calamities that have developed in the country for the last 22 years. Because of their wrong licensing policy and their attitude towards the economic development of the country they were responsible for the building up of big monopolies, 73 big monopoly houses, and non-removal of the regional imbalance in the industrial development of the country.

Now they have come forward with a Report wherein they mention that they have achieved something spectacular. Though I have tried my level best to find out whether there is anything spectacular in the report, I have to concede that I have not found anything spectacular in the report; on the other hand, it shows only the bankruptcy of the policy of the government. Instead of Ministry of Industrial Development, I would call this Ministry "the Ministry of Industrial Stagnation".

What is the achievement of this Ministry? What have they done all these years? What is their policy? All their tall talk of socialism is only in name. Whenever it comes to the question of getting a licence, the poor ordinary manufacturer has no chance or place; he will not get a single licence. All the licences will go to the big industrialists.

Even after the Syndicate-Indicate fight, a licence for the Goa Fertilizer project was given to the Birlas. When I moved a Private Members' Resolution in this House for a probe into the Birla affairs, Shri Fakhruddin Ali Ahmed came and defended the Birlas and defeated my resolution. Afterwards, he had the wisdom to order a probe now.

Now what is happening? Birlas are removing their papers from Calcutta. So, your so-called inquiry is going to be only a farce. What have you done with the Vivian Bose Commission Report? Have you implemented the recommendations of the Vivian Bose Commission? No, you have not done it. At the same time, you want to whitewash the situation. So, you are only cheating the people by saying that you are socialists. Whenever any licence is to be given, you give it only to the big monopoly houses and not even one licence to the ordinary people.

If my information is correct, Birlas have paid Rs. 1 crore to the offers of the Indicate to get the Goa Fertilizer project. Similarly, when the Punjab Government wanted to get a licence for a polyster fibre plant, they gave it to Jaipurias. I make the charge that this licence was given to Jaipurias for having some kind of political influence over them. Otherwise, why was it not given to the public sector?

When we look at the industrial policy for the last 22 years, is there any change in this policy at any time? No, nothing. Everything is the same.

I come from a most underdeveloped State, Kerala. Our Government has recommended some 25 licences to be given but not a single licence was given. We are prepared to produce small cars, scooters and many other things—I do not want to mention all those things because I do not have much time. In Calicut we have got iron ore and we wanted a steel plant. But you are not giving anything. You are specially neglecting Kerala. We are educated and unemployed. 20,000 diploma-holders and more than 5,000 engineers are rotting in the streets of Kerala without employment and you are not giving anything for us.

For the last ten years the Central Government was promising to give us a shipbuilding yard. I come from that place, Cochin. We were expecting the shipbuilding yard for the last ten years but nothing happened. Last year the citizens of Cochin City built a paper ship and launched it into the backwaters of Cochin to show our protest. Next year we will invite Shri Fakhruddin Ali Ahmed to launch our second ship.

Unemployment is so colossal and we are not getting a single employment opportunity. If we go outside, to Bombay, Shri Chavan's Shiv Sena is there which says, "You should not come to Bombay." The mulki movement is developing everywhere.

You want self-sufficiency in our State but you are not giving an iota of development to my State. You are talking about national integration but this tall talk of national integration is not going to solve the problem.

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali): They will give you fisheries now.

SHRI VISWANATHA MENON: Even on the question of fisheries, the Central Government is making money and getting foreign exchange by exporting our fish. Even our frogs are sold to foreign countries and you are getting foreign exchange. Our cardamom, our pepper and all our cash crops are being sold in foreign markets and you are getting foreign exchange. But when the question of giving even a small sector factory comes, you are not prepared to give anything.

You are talking a lot of things about national integration and all that. We have got the inferiority complex. We feel that we are being treated as second-rate citizens of this country. Kerala cannot be the colony of these Delhi Badshahs. Do not think like that; we are not going to be the colony of the Delhi Badshahs. We have got our own cash crops, fish and frogs and you are making money out of that. You must give us our due share and industry in the public sector.

We have got ample skilled manpower. After the Sabarigiri and Idikki projects, our electric power will also be abundant. On the one side there is manpower and on the other there is electricity. To combine these two, please give us some industry and consider we people as your equals. If you do not do that and treat us as second-rate citizens, I cannot say what is going to happen tomorrow in that area. Kerala has always been a pioneer for many new movements. I do not want to exaggerate it but I am telling you frankly that Kerala is in a very pitiable condition. So, I request the hon. Minister to come forward and declare here itself that of the 25 licences that have been asked for by the Kerala Government, you are prepared to give at least one. You make that declaration here. That is my humble request.

I want to conclude my speech by saying that if you are not going to change the industrial policy of this Government basically, you are not going to reach anywhere. First you must change this regional imbalance. You are now concentrating industry in certain developed areas only. The hon. Minister is coming from Assam and the other hon. Minister from another industrially backward area, Andhra. Why not we combine together against these big people and try to develop the backward areas? Let us combine together against these industrial monopoly areas—Maharashtra, Bengal and other big areas. Let us combine our resources and change the policy. That is my humble submission to the hon. Minister Once more, I appeal to him, don't forget Kerala, give at least one licence and declare it here and now.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : सभापति महोदय, हमारे देश में पहले ही बड़े छोटे के बीच बहुत अन्तर है और इधर कुछ समय से यह अन्तर और भी बढ़ता जा रहा है। जो धनवान है वे और धनवान होते गए हैं और जो निर्धन हैं वे और भी निर्धन बने हैं। इस प्रक्रिया में कई क्षेत्रों में मौनोपोली उत्पन्न हुई है और देश की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक शक्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केन्द्रित हुई है। यह सिलसिला इसी प्रकार और इसी दिशा में चलता रहा तो खतरा इस बात का है कि देश में जनतन्त्र ही समाप्त हो जाए और संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकार नष्ट हो जाएं।

सभापति महोदय, मुझे इस बात पर प्रसन्नता होती है कि इस खतरे को स्वतंत्र पार्टी के भी नेताओं ने पहचाना है। इस संदर्भ में मैं श्री सी० सी० देसाई को बधाई देती हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी में जो मौनोपोली के रक्षक हैं; उनका विरोध किया है और इस प्रकार देश की आर्थिक व्यवस्था को जनतन्त्रविरोधी शक्तियों से बचाने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, मेरे और मेरी पार्टी के सैद्धान्तिक विचार श्री देसाई से भिन्न हैं, परन्तु मेरा विश्वास है कि मौनोपोलीज को प्रोत्साहन देने वाली विचार धारा को जड़ से उखाड़ फेंकना आज सब दलों के लिए और समूचे देश के लिए अनिवार्य हो गया है। मौनोपोलीज के कारण जन साधारण की बड़ी हानि होती है और लगभग परिणाम वही होता है जो डिक्टेटरशिप की व्यवस्था में होता है। स्वतन्त्र पार्टी को मसानी साहब मौनोपोलिस्टिक शक्तियों की रक्षा और उनके हितों को आगे

[श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा]

बढ़ाने वाला वाहन बनाना चाहते हैं। उन्हें जन साधारण के हितों की चिन्ता नहीं, जनतन्त्र के भविष्य की परवाह नहीं। यह बड़े ही खेद की बात है। ऐसा लगता है कि मसानी साहब को गुजरात की सरकार से सट्टा बट्टा बनाए रखने की जितनी चिन्ता है, अपनी पार्टी की आबरू बचाने की उतनी चिन्ता नहीं है। उनके समर्थक राजाजी के बारे में तो जितना कम कहा जाए, उतना ही अच्छा है। राजाजी का सारा दृष्टि-कोण नेहरू परिवार के प्रति घृणा से अनुप्राणित है, उनकी और कोई दिशा नहीं, कोई ध्येय नहीं। आजकल तो सुनते हैं कि श्री कामराज की भी राजाजी से गाढ़ी छन रही है। देखना होगा कि व्यक्तिगत विरोध की भावना और क्या क्या रंग लाती है।

श्री सी० सी० देसाई को समाजवाद पर विश्वास हो या न हो, हमारे दृष्टिकोण से वे भले ही सहमत न हों, पर मौनोपोलीज के विरोध में उन्होंने जो रवैया अपनाया है, वह अवश्य देश के हित में है और अत्यन्त सराह-नीय है। उनके विचार पहले से भी ऐसे ही हैं और कोई आश्चर्य नहीं कि स्वतंत्र पार्टी में जो मौलिक अन्तर्विरोध था, वह प्रकट हुआ है और सिद्धान्त की दृष्टि से वहाँ भी मंथन शुरू हुआ है।

अब मैं मौनोपोली प्रेस के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मौनोपोली इनक्वायरी कमि-शन ने अपनी रिपोर्ट के पेज 186 में यह कहा है :

"Connection of big business with the Press has an unhealthy influence on society in as much as it obstructs the free formation of public opinion and moulds people's minds in the manner unduly favourable to the selfish interests of businessmen."

इस खतरे को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं? मैं समझती हूँ कि कुछ भी नहीं उठाये हैं। रेस्ट्रिक्टिव का जो एक्ट हमने इस सदन में पास किया था उसमें भी इसको चैक करने के कोई कन्क्रीट प्राविजंज नहीं हैं। श्री दत्त की मौनोपोली इनक्वायरी कमिशन ने बताया है :

"That there is the need for the study of concentration trends in the field of Press as also that of Monopolistic and restrictive practices therein.

(2) That the problem of Press is not to be viewed merely from the constitutional angle but is to be approached from the premise that in the Press world as in other fields of business there is a danger of small man being stifled or even thrown out by the weight of resources of dominant concerns by big business."

नेहरु जी ने 1963 में कहा था :

"The threat to freedom of Press may arise from power of money as represented by Press Monopolies. It is amazing how a few people have come to control so many newspaper chains and groups and how efforts are being made to confuse issues by equating their own freedom with freedom of Press."

इसलिए मैं समझती हूं कि प्रेस पर भी समाज का अधिकार होना चाहिए। उन्हें भी समाज के हित में काम करना चाहिए। सरकार ने उद्योगों में मैनेजिंग एजेंसी खत्म कराई हैं। उसे प्रेस उद्योग के मैनेजिंग एजेंसी को भी खत्म करना चाहिए। समाचारपत्रों के कर्मचारियों को भी समाचारपत्र उद्योग में शेअरहोल्डर बनाया जाए तो इस उद्योग से मौनोपोली खत्म करने में सहायता मिलेगी और राष्ट्रीय एकता भी बढ़ेगी।

एक बात मैं अपने आन्ध्र प्रदेश के बारे में कहना चाहती हूं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से आंध्र राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी अभी केरल के एक माननीय सदस्य बोले हैं और उन्हों-ने भी बताया है कि केरल बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। आंध्र को इंडस्ट्रियल सैक्टर से सिर्फ 8.5 प्रतिशत इनकम होती है जबकि इस इनकम का नैशनल एव्रेज 18 प्रतिशत है। पर कैपिटा इनकम भी नैशनल एव्रेज से कम है। जहाँ तक पर कैपिटा इलैक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन का

सम्बन्ध है, मद्रास की जहाँ वह 80 है और नेशनल एवरेज जहाँ 40 है, वहाँ आंध्र का सिर्फ 30 ही है। रिजनल इम्बैलेंसिस को खत्म करने के लिए यह आवश्यक है कि आंध्र में कुछ इंडस्ट्रीज लगाई जायें। केरल में इंडस्ट्रीज लगाए जाने के बारे में अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ कि छोटी कार प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद एक बहुत ही उपयुक्त स्थान हैं। हैदराबाद की क्लाइमैटिक और ज्योग्रेफिकल कंडिशंज इसके बहुत उपयुक्त हैं। वहाँ अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हैं। हैदराबाद इसके लिए एक आदर्श जगह है। मैं विनती करती हूं कि इस प्रोजेक्ट को वहां लगाया जाए।

आंध्र प्रदेश में कागज उद्योग का भी विकास हो सकता है, कागज का कारखाना भी वहां लगाया जा सकता है। बोदन में निजाम शूगर फैक्ट्री है। उसमें बगास काफी मात्रा में मिलता है। यू०एस०ए० की एक फर्म ने बताया है कि बगास से कागज बन सकता है। इसके वास्ते पहले सैंट्रल सैक्टर में प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान था। बाद में मालूम नही क्यों इसको छोड़ दिया गया और स्टेट सैक्टर में शुरू करने के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि पब्लिक सैक्टर में इस प्रोजेक्ट को आप वहाँ लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बाबूराव पटेल ने संजय गांधी को स्माल कार प्रोजेक्ट देने के बारे में कुछ कहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर बिड़ला, टाटा और जयपुरिया आदि को विभिन्न प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, तो क्या एक अनएम्पलायड टैकनीशन को सिर्फ इसलिए कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलना चाहिए कि वह प्राइम मिनिस्टर का पुत्र है। मैं इस समय स्माल कार प्रोजेक्ट के बारे में नहीं कह रही हूं। अगर उन्होंने एप्लाई किया है, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का पुत्र होना कोई गुनाह नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या कान्ति देसाई होना गुनाह है ?

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : वह दूसरी बात है।

एक अनएम्पलायड टैकनीशन को काम देने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या उनको इसलिए जीने का हक नहीं है कि वह प्राइम मिनिस्टर का पुत्र है ?

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): At the outset I must say that the Report produced by this Ministry appears to be a hackneyed one repeated from year to year. I have seen some of these reports and I have seen the present report also. I find there is always the same excuse whenever there is lack of production or loss in production. Whenever production goes down, the excuses given are these: lack of material, recession and finally, last but not least, that of labour troubles. Put all the blame on the labour troubles for any decrease in production in any sector whatsoever. It has already been stated by some hon. Members that this Ministry is not a development ministry because there has been no development so far. I will show how in many of the important sectors, private and public, production has gone down. Where is development? If there is no development, the style of the Ministry as Industrial Development Ministry is a misnomer. The rate of growth as stipulated in the 4th Plan is 9%. It says that this 9% rate of growth will be achieved in certain ways. But then what has happened? The Economic indicator shows that in transport equipments it has gone down over the last year by 2.2%; in Railways by 3.3%; in Footwear, wearing apparel, and made-up textile goods 4.9%; in synthetic fibre 3.2%; in leather and fur products 11.6%; textiles 4.4%; and in jute textiles 28.6%. This is the rate of growth in some of these major sectors. I will give you other examples. Just look at this Report. A close look at this Report will show that in as many as 200 items production has gone down. What is the cause? In some cases, the report says, the reason is lack of raw materials like formaldehide, synthetic resins in plywood industry and sometimes lack of stock. These are lame excuses on which the Ministry should not rely.

We come to another questi on whether the Ministry has justified its own image when it says that import substitution is going on

[SHRI SRINIBAS MISRA]

apace. Thre is another bragging at page 5 of the Report. It says: "The policy of export promotion has been vigorously pursued" For how long is this being vigorously pursued? Export has gone down, but at the same time, it is said here, 'The policy of Export promotion is being vigorously pursued.' So also about import substitution.

Foreign collaboration is going on in full swing as before. And new collaborators are coming in, perhaps, under conditions which are less favourable to India—less favourable than the previous conditions. In this Report you will find that in matters where there is a loss in a public undertaking, the figure is not given. Alternatively, they try to avoid giving that figure. Only the production figure is given. The loss is not shown at all. That has been the intention of the Ministry—I do not want to attribute any motive and it appears to me that had these figures been given, we would have been in a position to judge the performance of this Ministry. In some cases, the figures are mentioned. But, in the year 1968-69, it is left blank.

To come to the actual production, 9% increase is shown according to the Fourth Five Year Plan. It has also been admitted that the capacity has increased by 50% . But, Sir, you will see that when the increase in capacity is to the tune of 50%, the decrease in production is as I have shown earlier. It will be really ridiculous if the ministry says that our production has gone on increasing and it is always on the higher level. I may be permitted to give another figure. That is regarding the matches. In 1968, the increase was 9.5% but in 1969 it has gone down by 4%. Similarly, for the industrial machinery, the increase in 1968 was 19.1% but in 1969 that has gone down. There is a decrease of 14.4% in bicycle. In 1968 504 thousand cycles were produced but in 1969 only 429 thousand were produced. Similarly, power transformers worth 1240 thousand kilowatts were produced, but in 1969 it has come down to only 1,942 thousand kilowatts. 437 thousand electric fans were produced in 1969. Production of electric motors has also gone down. Radio transmitters' production has also gone down; production of art-silk fabric has also gone down. They say it is an exchange order. It has gone up to 18 million metres.

Regarding the dispersal of industries, many reports of the Working Group have been circulated. The Working Group says that there are backward areas—un-developed areas. As already suggested by some hon. Members, industries should be set up in these areas. So far as my own State is concerned, I shall only represent one case—the case of a jute mill in Orissa. Orissa is a coastal area which produces enough of jute to feed more than one jute mill and the people there have been representing the matter time and again. Government of Orissa also have written very recently—not very recently but about one year back—that a cooperative society wanted to establish a jute mill in the district of Cuttack and it wrote to the Minister also. We also asked a question about that. What has the Minister done about that? The Minister has come out in his reply that the Ministry have not received the representation. It is strange that a representation that was circulated to all the M. Ps of Orissa reached them but that did not reach the Minister to whom it was addressed.

SHRI R. K. BIRLA: Send a copy of that to him.

SHRI SRINIBAS MISRA: Whatever it may be, I would say that Orissa justifies itself to establish a jute mill. It is really useless to ask the farmers to sell their jute to the middlemen who transport that to Calcutta where the jute goods will be manufactured. The transport cost will be there. The middlemen are sucking the producers at their own price. They name their price and if the producers do not sell at that price, they do not sell at all. In order to eliminate the middlemen, a jute mill should be sanctioned and licensed with all possible help in the district of Cuttack where enough jute is produced to feed one mill.

There are other small extractive industries like myrobalan extracts and nux vomica extracts and other forest-based industries for which raw material is available in plenty in Orissa and should be encouraged.

Regarding small scale industries, whatever is being said on the floor of the House or stated by government spokesmen in papers is really a myth. We hear that financing facilities are being given to the small scale sector and integrated plan studies have been undertaken, consultancy services provided and so on. But we do not find any of these services in such backward areas as Orissa. These are all promises and achievements on paper only or in statements by Ministers here.

The handloom sector is not being sufficiently protected. It was stipulated by rule that the powerlooms should not produce coloured saris. But we see that this provision is not being strictly implemented. Coloured saris are being produced by powerlooms and passed off as handloom saris. As a result, many handloom weavers who weave coloured saris are without employment. When they go to the market, the buyers do not buy them but the powerloom produced sari as it is cheaper.

Regarding restriction of monopoly, I welcome the legislation enacted. It is also a welcome feature that Government have declared as a policy to help and give licences to unemployed engineers to start new industries. But the last report of the Inquiry Commission on the Birla group reveals many cases where licences were given to the Birla group, and a licence was given for a factory at Mirzapur even before they applied for it.

Regarding auditors, they are really expected to expose things in detail whatever they find in the companies books of accounts. But we find many of them, specially those attached to big concerns, do not function like that. They try to suppress facts and figures as the Ministry has tried to do in this report. Rules must be framed to regulate the auditing procedure as has been done in the case of cost accounting regarding various industries. It should be made fool-proof so that auditors should be compelled to bring out all the facts and not conceal them.

SHRI S. S. KOTHARI: May I point out that this is an unwarranted attack on auditors? He is speaking without understanding facts. I should like to put on record that he has attacked the profession without understanding facts. He does not know that there is a disciplinary commitee to punish erring members.

SHRI SRINIBAS MISRA: I did not attack the profession. I made that statement about some people attached to big firms.

SHRI S. S. KOTHARI: He is trying to cast a reflection on an honourable profession.

SHRI SRINIBAS MISRA: Not at all.

SHRI S. S. KOTHARI: As an intelligent member and a lawyer, he must study the whole problem, how they function and then make remarks. There is the Institute of Chartered Accountants to take the strongest possible action against those who are black sheep.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY): In the course of the debate today Shri S. M. Banerjee referred to some matters connected with Shri Ram Nath Goenka. I may inform the House that the CBI registered the First Information Report on 14th February, 1970 and after making necessary arrangements, raided some places at Calcutta and Madras including the residence of Shri R. N. Goenka on the 25th and 28th March, 1970. They have taken into custody a large number of share certificates of the Indian Iron & Steel Co., and some other documents for scrutiny. Therefore, the matter is with the CBI. I hope the hon. House will not press me to go into the matter further.

One of the hon. Members has raised the question of company donations being paid in the form of advertisements to the souvenirs being published by various political parties. This matter is covered by the Company Law itself, and a circular has been issued to all the Chambers of Commerce and other organisations concerned drawing their attention to the provisions of the law. If there is any departure from or violation of the law, then the law will take its own course.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): बम्बई कांग्रेस के सोविनार के लिये हमने तीन महीने पहले लिखा था, आपने क्या किया?

SHRI S. S. KOTHARI: The donations are given in the form of advertisements. Mr. Mrityunjay Prasad pointed out some instances.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The law is quite clear on the subject. I need not say in what manner it should be implemented. If there is any violation of the law, certainly the law will take its own course.

Another point that was raised is about the *Samachar Bharti*. The Registrar of Companies is looking into the matter, and certainly whatever action is called for will be taken by him.

Yesterday Shri Himatsingka had raised two questions. The main obsession of Shri Himatsingka seems to be the dominant undertaking and the inter-connected undertaking under the Monopoly Law. The definition of dominant undertaking covers one-third production or services, and if a dominant undertaking is to fall within the four corners of

[SHRI RAGHUNATHA REDDY]

Chapter III of the Monopoly Law, the law is also clear on the subject. I do not think that a wise man like him should have raised this question.

About inter-connected undertakings, the question that has been raised is that the definition is so wide that it will cover many things under the Sun in India. I am afraid that, even there, Shri Himatsingka committed a grave error in interpreting the law. After the abolition of the managing agencies, I am afraid that the definition itself has become a little anaemic and we are examining the question. If the examination warrants it, we may have to strengthen the definition instead of weakening it. Therefore, the fear expressed by him is unwarranted.

Shri Patodia has presented to us a mythology of capitalism in India and has made out three points. One is that the money that is being taken by the private sector companies from the public sector financial institutions is not the property of the Government. Certainly not. Nobody claims that it is anybody's grandfather's property. This money belongs to the people, and under the law and the Constitution, unless one goes back to primitive society,—I think even the primitive society had some sense of social organisation—or unless one becomes an anarchist completely, the political theory of the State will have to be followed, and it has been accepted as an axiomatic proposition, from the 17th century onwards that the State has got the right; in fact the State has got an obligation to intervene a public interest in the economic affairs of society as it represents the interest of the people. This proposition has been accepted by the proponents of the welfare State or the capitalist State, let alone those who believe in the history of the socialist State. Therefore, this proposition has no validity.

He also tried to make us understand that there was distinction between paid up capital and assets. If the assets are increased by 100 or 200 per cent, the assets should not be mistaken to be the property of the particular group of individuals. Therefore, he blamed us that we were trying to present a misleading picture in Parliament by saying that a certain group of individuals owned certain assets. I am afraid he should credit us that we are capable of drawing a distinction between paid-up capital and assets. If he carefully reads the Monopolies Inquiry Commission Report, he will see that it clearly conceived that the paid up capital or the assets should not be so held as to extend the control of a single individual or a group of individuals over the resources of the community. The report itself states that the problem is one of concentration of economic power; restrictive and monopolistic practices are the results of concentration of economic power. If we understand the concept of assets in this context, Mr. Patodia's theory has no basis. It is only a myth of private capitalism. The Monopolies Commission report says on the first page itself: "Clearly concentration of economic power is the central problem. Monopolistic and restrictive practices may properly be considered to be the functions of such concentration.

Mr. Patodia asked: what is wrong in the companies taking money? As a general proposition there is nothing wrong. What do they do with this money? How do they get it? Would there be any misdirection in investment of resources? Would there not be proper channelisation of money into proper developmental activities in the interest of the people? These are broad questions. I have no quarrel with anybody who engages in useful activity, increasing production and productivity and working in the interest of the people. If on the contrary money is taken in the form of loans, debentures, etc. and is utilised for building up financial empires and extending their imperial hold over corporate sector, the difficulties, arise. I do not think that any person with any knowledge of the subject would allow such practices to prevail. This is what exactly we are trying to prevent by various laws—nothing more.

He says that we are against competition. Certainly not. I shall quote one sentence from memory; one of the sentences used by Mr. C. C. Desai in his letters was to this effect: The pillars of private enterprise do not want competition because they stand to gain by monopolistic practices. It is they who indulge in monopolistic practices by building monopolistic empires against free competition. We try to restrict those empires and enlarge the field of competition in the private sector by allowing corporate bodies to increase production. It would be a folly in economic theory to attribute any monopolistic features to the public sector because there is nothing like monopoly in economic theory as far as the public sector is concerned.

SHRI S. S. KOTHARI: State monopoly.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: There is nothing like a State monopoly. Whatever the State owns is the property of the people. Therefore, there is nothing like a monopoly as far as the State is concerned. The concept of monopoly would arise only in terms of the private sector and not in terms of the public sector.

SHRI S. S. KOTHARI: They misuse their economic power, including Ministers.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Shri Patodia had also said that we are still clinging to the classical concept of monopoly, and we are not able to understand it properly; that is what he had said, if I have understood him properly. Again, I would feel rather hesitant to mention some small mistakes in economic theory, but I consider it my duty to tell the House, because the point had been made out already. At present, there is nothing like a classical type of monopoly as it is etymologically understood. What is now prevalent is duopoly, oligopoly, like cartels and combinations, large forms of monopoly which have manifested themselves in different incarnations controlling the economic life of this country.

SHRI SRINIBAS MISRA: Not polypoly?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Yes; that also. It is something in the nature of a polygamous development. (*Interruption*) It is in this context that the problem of monopoly will have to be understood.

SHRI S. S. KOTHARI: Economic power becomes concentrated in the hands of Ministers, which I call Ministropoly. This is flourishing in this country to the detriment of the people of this country.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Since some points have been made out, I will try to illustrate from facts. The aggregate assets of the 75 houses were of the order of Rs. 2,606 crores in 1963-64, of which Rs. 1,780 crores, that is, 68 per cent, were accounted for by the 20 large houses, and Rs. 826 crores, that is, 32 per cent, were accounted for by the remaining 55 houses. I am only trying to deal with the 75 houses.

Sir, the question arises: how do these houses get their money, and is there any truth in what Shri Patodia had said. If we look at the Reserve Bank bulletin published in December, 1968, it will give a very vivid picture as to how these financial operations took place in the world of scheduled commercial banks before nationalisation was done, for which purpose nationalisation is completely justified.

I will give only a few figures. I do not want to strain the hon. Members by giving elaborate figures. For instance, from the figures available as on 31.3.1967, I hope the hon. Members who specialise in accounts would understand, in the year 1967, 437 individual accounts have taken Rs. 635.37 crores accounting for 23.4% of the total loans. Then, the Reserve Bank people could not calculate the percentage from the total accounts—664 accounts—0.1 per cent of the total number of accounts—have taken Rs. 369.25 crores. Then, 0.4 per cent have taken Rs. 668.05 crores as loans. I do not want to strain further by giving more figures.

SHRI S. S. KOTHARI: How much production do they account for, and what is the ratio of production to the loans in the private sector and the public sector? Please arrive at those figures, and you will grow wiser. What is the amount of production, and how does it compare with production in the public sector, compared to the loans they have taken? Do not challenge. You are a theoretician; that is all.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I am only trying to deal with the real contribution made by the public sector on its own and in what manner they had drawn on the public exchequer in order to achieve—(*Interruption*)

SHRI S. S. KOTHARI: Loss of Rs. 35 crores on an investment of Rs. 3,500 crores.

SHRI RAGHUNATH REDDY: I know he is a very intelligent man. He can put all these questions on a different occasion. The total deposit with the bank as on 31st March 1968 amounted to Rs. 3994.6 crores. Of this, deposits owned by Government, Government-controlled institutions, individuals and cooperatives amounted to Rs. 2930 crores, which forms 73 per cent of the total deposits. I am quoting it with a purpose. The money which has been deposited in the bank generally belongs to the public. The actual contribution made by limited companies in terms of fixed deposits made, according to the Statistical Tables Relating to Banks in India in 1968, is 4.3% by industry and trading and 0.1 per cent, by other limited companies. Having made this contribution they take nearly 60 per cent of the total deposits either by way of loans, ad-

[SHRI RAGHUNATHA REDDY]

vances and other contributions made to the private sector. This is how banks have been used. This is how the financial institutions have been used for the purpose of benefiting the private corporate sector. This is the philosophy which Shri Patodia had tried to present yesterday. This would show in what manner they would exploit and also develop a mythology around it to justify the exploitation which they have indulged in.

One point was raised by Mr. Kothari regarding the small-scale sector. I must pay my compliments to the small-scale sector. It has got a share of 35 per cent in the entire total production of the country. One point has been asked, what is meant by concentration of economic power. No doubt concentration of power has not been defined by any text book or by statute so far. But I will quote Mr. R. H. Tawney from his great work *Equality*, which would give some idea of what is meant by concentration of economic power. With your permission, Sir, I would quote him :

> "Power may be defined as the capacity of an individual, or group of individuals, to modify the conduct of other individuals or groups in the manner which he desires, and to prevent his own conduct being modified in the manner in which he does not ...in an industrial society, the tendency of economic power is not to be dispersed among numerous small centres of energy, but to be massed in blocks. It is gathered at ganglia and nerve-centres whose impulse gives motion to the organism and whose aberrations or inactivity smite it with paralysis. The number of those who take the decisions upon which the conduct of economic affairs, and therefore, the lives of their fellowmen, depend is diminished; the number of those affected by each decision is increased."

This is the essence of concentration of economic power. That is why the concept of assets will have to be understood in the context of growing concentration of economic power and not as a ratio between paid-up capital and assets, saying that the assets after all belong to the lakhs of shareholders. It should be understood that even in the case of paid-up capital, though the shareholder is theoretically expected to participate in the shareholders' democracy, it is seldom that a small shareholder would be able to exercise this right to shape or even correct the policies of a corporate body. Therefore, there is not much substance in the argument that the shareholders' democracy is there and therefore, all the shares belong to the shareholders.

It must be made clear that Government is not opposed to the private sector as such. The Government is opposed only to the manifestations of concentration of economic power and to monopolistic practices and various other forms in which malpractices persist. Having advocated the philosophy of mixed economy, we wish the private sector well; we wish the private sector to prosper, provided it acts within the ambit of the limitations that have been placed upon it in the interests of the community and the people. Otherwise once the private sector is allowed to grow to such a length, once concentration of economic power is allowed to grow to such strength where it would be able to influence the politics of the country, I am afraid the liberty of democracy itself is in danger.

I will conclude by showing why I say that democracy is in danger. I want to quote the message that President Roosevelt sent to the Congress while they were appointing the Temporary National Economic Committee to go into the problems of concentration in America. The message reads thus :

> "The liberty of a democracy is not safe if the people tolerate the growth of private power to a point where it becomes stronger than their democratic state itself. Concentration of economic power ... and the resulting unemployment of labour and capital are inescapable problems for a modern private enterprise democracy."

That was the message of President Roosevelt.

Sir, I will say with great humility that the social transformation is on the agenda of our history and whatever might be the dissenting voices and the forces of *status quo* that may be set in motion, the socialist transformation cannot be stopped. The inexorable march of history, the inexorable march of the people, cannot be stopped by these forces.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी की समाजवादी सरकार तकरीबन पाँच साल से सत्ता में है और औद्योगिक विकास मन्त्री भी तीन साल से इस मंत्रालय को देख रहे हैं लेकिन इन पांच वर्षों का अगर

[श्री मधु लिमये]

लेखा-जोखा लिया जाएगा तो औद्योगिक विकास के लिए या इस मंत्रालय के लिए जो सर्वसाधारण उद्देश्य होने चाहिए उनमें से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है—यह बात बिल्कुल साफ हो जायगी।

जहाँ तक भारत की खेती का सवाल है वह तो मौसम के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन जहाँ तक औद्योगिक मंत्रालय का सवाल है उसका कर्तव्य होना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन में अधिक गति उत्पन्न करने का प्रयास करे लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि 1966-67 में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के बजाय घटा और उसके बाद 1968-69 में 6-7 प्रतिशत बढ़ा है तो अगर चार साल का लेखा-जोखा लेंगे तो तीन साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक औद्योगिक पैदावार की गति नहीं बढ़ी है। क्या मन्त्री महोदय इसको सफलता कहेंगे? तो पैदावार बढ़ाने के मामले में यह मंत्रालय बिल्कुल अयोग्य साबित हुआ है।

दूसरा उद्देश्य आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। क्या इस के बारे में मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि आर्थिक सत्ता को विकेन्द्रित करने के लिए, वितरित करने के लिए इनके मंत्रालय के द्वारा कोई ठोस काम हुआ है? कई कमेटियाँ बनीं, उनकी रपटें आयीं, लेकिन जहाँ तक औद्योगिक ढाँचा हमारे देश में है, और जो आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण है, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आया।

बम्बई कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने के बाद जिन तीन नीतियों की घोषणाएँ की गयीं, उनमें एक घोषणा थी कि गोआ में बिड़ला जी को फर्टिलाइजर का कारखाना दिया जाय, इस्पात के दामों को बढ़ाया जाय और वनस्पति घी के दाम भी बढ़ाये जायें जिसमें हिन्दुस्तान लीवर जैसी विदेशी कम्पनी का अकेले उत्पादन में एक तिहाई हिस्सा है। तो सत्ता के केन्द्रीकरण का जहाँ तक सवाल है पुरानी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया और समाजवाद के नाम पर मुल्क में एकाधिकारशाही को उत्पन्न करने का जो काम 23 साल से चल रहा है, पिछले तीन, चार वर्षों में उस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

इन्होंने कम्पनी कानून में हम लोगों के कहने पर परिवर्तन किया और मैनेजिंग एजेन्सी की प्रणाली को, तथा कम्पनियों के द्वारा जो राजनीतिक दान दिया जाता था, उस प्रथा को भी बन्द करवाया। लेकिन जैसा कि उस समय हम लोगों ने कहा कि यह बिल तो पास हो जायगा लेकिन उस के बाद कम्पनियाँ नये नये रास्ते निकालेंगी जिस से जो पुरानी प्रथायें हैं वही चलती रहेंगी, वह बात हमारी सच साबित हो रही है।

अब राजनीतिक अनुदान के बारे में उन्होंने कहा कि कानून बिल्कुल साफ है। लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही नहीं है, उनका ध्यान इन बातों की ओर हमने तत्काल आकर्षित किया था कि सूवेनेयर के जरिए, यानी जो सप्ताह के नियमित ढंग से अखबार नहीं निकलते हैं, जो मासिक पत्रिकाएँ नहीं हैं, ऐसे राजनीतिक दलों के सूवेनेयर्स को इतनी बड़ी मात्रा में विज्ञापन दिये जाते हैं कि कम्पनी के राजनीतिक चन्दे को बन्द करके जो फायदा होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कितनी कम्पनियों के खिलाफ आप ने कार्यवाही की है? या सिर्फ यह आश्वासन ही देते रहेंगे कि कानून बिल्कुल साफ है और कम्पनियों का ध्यान इस ओर खींचा गया है?

मैनेजिंग एजेंसी की प्रणाली को खत्म इसलिए किया गया, कम से कम मैंने विधेयक इसी दृष्टि से रक्खा था कि निजी क्षेत्र में सामन्तवाद का, परिवारवाद का जो असर है वह खत्म हो और जिन को तकनीकी ज्ञान है, बिजनेस का ज्ञान है, ऐसे नए नए लोगों को काम में लिया जाय, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का विकास किया जाय। लेकिन क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली को खत्म करने के बाद रत्ती भर भी

परिवर्तन हुआ है? मैंने 8, 10 कम्पनियों के बारे में मन्त्री महोदय को चिट्ठियाँ लिखी हैं और उन से पता चलेगा कि जिन लोगों के हाथ में मैनेजिंग एजेन्सी थी उन्हीं लोगों को और उन के ही रिश्तेदारों को होल टाइम मैनेजिंग डायरैक्टर बनाया गया है। उस में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। इस मंत्रालय के द्वारा जो सम्पूर्ण समय दे कर काम करने वाले मैनेजिंग डायरैक्टर आदि लोग हैं उन को कितनी तनख्वाह दी जाय, उस के बारे में इन्हों ने एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र का इस्तेमाल कम्पनियों के द्वारा शेयरहोल्डर्स को और उपभोक्तओं को लूटने के लिये किया गया है। इस परिपत्र के बारे में मैंने छ. सुझाव इन के पास भेजे हैं, जिन की संक्षेप में मैं चर्चा करना चाहता हूं। सब से पहले मैं चाहूंगा कि पाँच साल के लिये इन मैनेजिंग डायरैक्टरों की नियुक्ति न हो, तीन साल के लिये हो। जैसे अन्य डायरैक्टर्स हैं उन के साथ यह भी बदल जायें। साथ साथ एक दो जगह मैंने ऐसा देखा है कि एक जगह पर होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर उसी को नियुक्त किया जाता है जो किसी एक दूसरी कम्पनी में पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर है। ऐसा गोकाक औ—आई० वी० पी०के बारे में मैंने लिखा है, लेकिन उस के बारे में मंत्रालय सो रहा है, कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है।

इसी तरह उन लोगों को सुविधायें क्या मिलें इस के बारे में एक सीमा लगाई गई है, लेकिन एक एक सुविधा के बारे में अलग अलग सीमायें नहीं लगाईं। नतीजा यह हुआ है कि एक कम्पनी से वह मोटर कार अलाउंस लेंगे, एक कम्पनी से दूसरा अलाउँस लेंगें और दूसरी कम्पनियों से दूसरी सुविधायें लेंगे। इसके बारे में मंत्री महोदय को सोचना चाहिये।

जो पुराने करारनामे हैं उनके बारे में भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और मैंने सुझाव दिया है कि पुराने सभी करारनामों को खत्म किया जाय और जो सुझाव मैंने दिया है या तो उसके आधार पर उनको नये सिरे

से बनाया जाय या अगर वे मेरे सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो कम से कम जो यह परिपत्र है उसके अनुसार उन में संशोधन करने का काम हम करें।

साथही साथ में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि नये नये लोगों को इन बड़े पदों पर पहुँचाने के खिलाफ मंत्री महोदय क्या कार्यवाई कर रहे हैं। आज कुछ लोगों ने सट्टा खेल कर चोरी करके, भ्रष्टाचारकरके कुछ कम्पनियों पर कब्जा किया है, जैसे कापड़िया के बारे में कुछ अर्से से मैं लिख रहा हूँ, उन की मैनेजिंग एजेंसी खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बम्बई सुबरबन एलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है, अहमदाबाद की कम्पनी है, सूरत की कम्पनी है, उनमें एक परिवार के रिश्तेदारों को होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त करने का सुझाव आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। इस मंत्रालय में जो चापलूसी करेगा, खुशामद करेगा या जो बड़े लोगों के रिश्तेदार होंगे उनके बारे में कभी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि मुझ से पहले श्री बाबू राव पटेल ने प्रधान मंत्री जी के लड़के को मोटर गाड़ी की पैदावार का लाइसेन्स देने के बारे में पूछा था। मैं आज मंत्री महोदय से एक ठोस सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोगों ने सुना है कि प्रधान मंत्री के लड़के ने एक गाड़ी का माडेल तैयार किया है जिस का इस्तेमाल भी हो रहा है। क्या इस गाड़ी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आदि जो कर हैं वह दिये गये हैं? अगर नहीं दिये गये हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जब पूँजीपतियों के परिवार इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो हम लोग चिल्लाते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री के लड़के के बारे में क्या इस मंत्रालय में या वित्त मंत्रालय में कार्रवाई करने की कोई हिम्मत है? अगर नहीं है तो साफ साफ कह दीजिये कि हमारा समाजवाद और शुद्ध शासन सारा ढोंग है और हम को मनमाने ढंग से काम चलाना है।

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : If it is a good model, what is the harm ?

श्री मधु लिमये : क्या एक्साइज ड्यूटी की चोरी करना अच्छा है ? मैं इस बारे में खामख्वाह आप से वाद-विवाद नहीं करना चाहता।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : If the model car is used, they must pay the excise duty and other taxes.

श्री मधु लिमये : अब आप बड़ौदा रेयन के मामले को लीजिये । उस ने ऐसी सब की तनख्वाहें और सुविधायें निश्चित की हैं कि आप दंग रह जायेंगे । मिनिमम रेम्यूनरेशन निश्चित करते समय उन्होंने कहा है कि मुनाफा हो या घाटा हो, उनको जो रेम्यूनरेशन मिलने वाला है उस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कम्पनी मंत्रालय इसको भी मान्यता देने वाला है ? मुझे डर है कि चूंकि एक मन्त्री का लड़का इस कम्पनी में होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर है इस लिए श्री फखरुद्दीन अली अहमद की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इस कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाई करें । उन के मंत्रिमंडल के मिनिस्टर का लड़का उसमें होल-टाइमर है।

आज ही कलकत्ते से मेरे पास चिट्ठी आई है जिस में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के बारे में कहा गया है। उस में तीन तीन लोगों को एक तिहाई प्रतिशत कमिशन देने का नया प्रस्ताव आया है। इस ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी में भी एक बड़े नये समाजवादी का कोई रिश्तेदार काम करता है। नया समाजवादी है वह । उससे मास्को में मेरी मुलाकात हुई थी । मैंने पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो लेनिनग्राड जा रहा हूँ क्योंकि वह रशियन क्रान्ति का केन्द्र था । उन्होंने कहा कि मैं स्टालिनग्राड जा रहा हूँ। मैंने कहा बात बिलकुल साफ है । तुम नये समाजवादी हो, मैं पुराना समाजवादी हूँ।

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के बारे में अभी मुझे चिट्ठी आई है और तीन तीन लोगों को इतनी ज्यादा सुविधायें और तनख्वाहें दी गई हैं और उसके साथ साथ यह कमीशन वाला मामला है।

17 hrs.

एक माननीय सदस्य : नाम बताइये ।

श्री मधु लिमये : केशव देव मालवीय नये समाजवादी और बड़ौदा रेयन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो श्री के० के० .शाह का लड़का है। आप मजबूर करते हैं नाम लेने के लिए।

मैं एक एक वाक्य में मुद्दे रखता हूँ। असल में बात यह है कि आज निजी क्षेत्र यानी कम्पनी सैक्टर परिवारवाद और सामन्तवाद से चौपट हो रहा है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके ऊपर यह सर्वसाधारण प्रशासक, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, आई० सी०एस०और आई०ए०एस०हावी हो गया है और कहीं भी निपुणता, विशेष गुण के आधार पर आगे बढ़ने का नौजवानों को मौका नहीं मिल रहा है इस लिए निजी क्षेत्र से भी कुछ नहीं निकल रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र से भी कुछ नहीं निकल रहा है।

दो तीन सवाल उठाये गये हैं। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो कर्जा दिया जाता था उसको इक्विटी में परिवर्तित करने के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। क्या मंत्री महोदय ने इसके बारे में कोई ठोस नीति अपनाई है।

दस दस करोड़ जो इस्को और टिस्को को दिया गया है वह मामला भी बहुत पुराना मामला है। उसके बारे में भी यहाँ पर बहस छेड़ी गई थी और सरकार को बताया गया था कि कानून में अधिकार होते हुए भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि बड़ी कम्पनियों के खिलाफ अपने अधिकार को इस्तेमाल करे। इसलिए वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो कर्ज दिया जाता है उसको इक्विटी में परिवर्तित करने के बारे में आपकी जो नीति है उसका आप यहां एलान करें।

अल्पसंख्यक शेअरहोल्डर्स को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में प्रतिनिधित्व मिले, इसके बारे में भी सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस सुझाव नहीं आया है । अगर सरकार स्वयं बिल लाने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम निजी सदस्यों के जो बिल हैं, उनके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिये ।

मैनेजिंग एजेंसी खत्म होने के बाद हमने इनको चेतावनी दी थी कि सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप

के नाम पर भी वही काम किया जाएगा। सिंथेटिक के बारे में हमने पहले सवाल उठाया था। अब उसी प्रणाली को तकरीबन दूसरी कम्पनियां भी अपनाने लगी हैं। इसलिए सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में भी सरकार जल्दी कोई कानून बनाए और कोई पाबन्दी लगाए। ऐसा नहीं किया गया तो मैनेजिंग एजंसी को खत्म करने के जो अच्छे नतीजे निकलने चाहिये थे, वे भी नहीं निकलेंगे।

समय अधिक नहीं इसलिए एक बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जो इनकी लाइसेंसिंग की नीति है, इससे न उद्योगों में स्पर्धा उत्पन्न हो रही है, न पैदावार बढ़ाने का मौका मिल रहा है, बल्कि जो खुशामद करेंगे, जो चापलूसी करेंगे, जो इनको चन्दा देंगे उन्हीं इने गिने लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मोदीनगर के गूजर मल मोदी को पद्म विभूषण वगैरह से इन लोगों ने विभूषित किया था। इतना ही नहीं। अभी मोदीनगर इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की राजयीय सरकार के आशीर्वाद से नतीजा यह हुआ है कि मोदीनगर में जब कभी श्रमिकों के बीच में और व्यवस्थापकों के बीच में संघर्ष हुआ है, कभी भी ट्रिब्यूनल को मामला नहीं भेजा गया है हालांकि सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। यह आप इसलिए कर रहे हैं कि मोदीनगर के सेठों के द्वारा राजयीय सरकार के नेताओं को और आप लोगों को भी मदद मिलती रहे। अगर ज्यादा मुझको छेड़ेंगे तो इन्दिरा गांधी जी के नाम से भी जो चैक वगैरह दिये गये हैं, उसकी जानकारी भी यथा अवकाश हम सदन के सामने दे देंगे और उसको भी हम देने वाले हैं।

श्री शशि भूषण (खारगोन): चन्द्र भान गुप्त जी से पूछिये।

श्री मधु लिमये: उनसे हमारा क्या रिश्ता। मैंने तो कहा है उत्तर प्रदेश की राजयीय सरकार, चाहे चरण सिंह की हो या चन्द्र भान गुप्त जी की। मुझे कोई मतलब नहीं है। एक दफा दोनों एक साथ थे।

श्री मु० अ० खां (कासगंज): पैम्फ्लैट केस में इन्होंने एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखी थी जिसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें दिया था। गिरि केस में इन्होंने उस चिट्ठी को सिंडीकेट को दे दिया है और इसको अदालत में पेश किया गया है।

**

श्री मधु लिमये: सभापति महोदय, इनको इसे वापिस लेने के लिए कहें, वर्ना इसके बारे में प्रिवलेजिज कमेटी में कार्रवाई करूंगा।

श्री मु० अ० खां: आप भी अपने अलफाज वापिस लें।

श्री मधु लिमये: क्यों ? उसे मैं साबित करने वाला हूं। आप भी करेंगे ?

श्री मु० अ० खां: करूंगा।

श्री मधु लिमये: इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है। मामला प्रिवलेजिज कमेटी में भेजा जाए। ये साबित न करें तो इनको इस सदन से निकाल दिया जाए।

श्री मु० अ० खां: इनको भी इस सदन से निकाल दिया जाए।

श्री मधु लिमये: बिल्कुल ठीक है।

श्री मु० अ० खां: प्राइम मिनिस्टर का खत नहीं दिया ?

श्री मधु लिमये: चोरी से नहीं लिखा है। प्राइम मिनिस्टर के काम की वजह से हमारे जीते हुए उम्मीदवार का चुनाव खतरे में पड़ गया है।

सभापति महोदय, मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मौका दीजिए। प्रधान मंत्री के कारनामों से हमारे द्वारा जिस उम्मीदवार का समर्थन किया गया था, और जो जीत गया था, उसका चुनाव

**Expunged as ordered by the Chair—*vide* col 232.

[श्री मधु लिमये]

आज खतरे में पड़ गया है। इस खतरे से बचने के लिए मैंने इलैक्शन कमिश्नर को एक पत्र लिखा था और प्रधान मंत्री को भी एक पत्र लिखा था, (व्यवधान) लेकिन प्रधान मंत्री ने मेरे पत्र के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की और उन्होंने गिरि साहब के चुनाव को खतरे में डाला है। (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर): यह उस प्रधान मंत्री की बात कर रहे हैं, जो मिंक कोट और हीरों का हार लेकर समाजवाद की चर्चा कर रही हैं।

श्री मधु लिमये: सभापति महोदय, आप इसके बारे में खुलासा कीजिए। मैं माननीय सदस्य को चुनौती दे रहा हूं। वह मेरी चुनौती को स्वीकार करें। अगर वह इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो वे अपने शब्द वापिस ले लें। या आप उन शब्दों को एक्सपंज कर दें, कार्यवाही से निकाल दें। (व्यवधान)

श्री मु० अ० खां: इन्होंने भी तो पैसा लेने की बात कही है। (व्यवधान)

श्री मधु लिमये: मैं तो राजनैतिक चन्दे की बात कर रहा था। या तो वह अपने रिमार्क को वापिस ले लें...

श्री मु० अ० खां: हरगिज नहीं।

श्री मधु लिमये: ..या आप इस मामले को प्रिविलेजिज कमेटी को भेजिये।

सभापति महोदय: आप उसके लिए कार्यवाही करें।

श्री मधु लिमये: यह सब कुछ आपके सामने हुआ है। आप उस रिमार्क को एक्सपंज कर दीजिए। वह नोटिस दे कर कहें। हम भी जवाब देंगे। इस बारे में कोई ठोस निर्णय होना चाहिए।

श्री रवि राय (पुरी): सभापति महोदय, आप को इस बारे में निर्णय देना चाहिए।

श्री मधु लिमये: आप इस को एक्सपंज करवा दीजिए। बाद में वह नोटिस दे कर कहें। हम को एतराज नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय: व्यक्तिगत आरोप लगाना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री मधु लिमये: मैं राजनैतिक चन्दे के बारे में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: वह रिकार्ड पर नहीं रहेगा। आप कनक्लूड कीजिए।

श्री मु० अ० खां: सभापति महोदय, आप उनकी कही हुई बात भी एक्सपंज कर दीजिए। उन्होंने भी कोई सुबूत पेश नहीं किया है। इन्साफ की बात यह है कि वह भी एक्सपंज होना चाहिए। अगर उनका रिमार्क रिकार्ड पर रहेगा, तो मेरा रिमार्क भी रहेगा।

सभापति महोदय: श्री नागेश्वर द्विवेदी।

श्री मु० अ० खां: सभापति महोदय, दोनों रिमार्क एक्सपंज होंगे न ?

सभापति महोदय: वह भी देख लेंगे।

श्री मु० अ० खां: तो फिर मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय: मैंने कहा है कि वह भी देख लेंगे। श्री नागेश्वर द्विवेदी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछली शहर): सभापति महोदय, मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सत्य है कि आजादी के पश्चात् इन तेइस वर्षों में देश में बड़े-बड़े उद्योग-धंधों की बहुत व्यापक पैमाने पर स्थापना हुई है और उन में अच्छी सफलता मिली है और उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

हमारे देश में आजादी के पहले औद्योगिक दृष्टि से देश की हालत यह थी कि बड़े बड़े कल कारखानों की बात कौन कहे, सुई और बटन तक बाहर से आते थे। लेकिन आज औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। बहुत इस

दिशा में काम हुआ है। मैं उसके ब्यौरे में जाकर अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन जो कुछ हुआ है उसी से हम को संतोष नहीं करना है। एक समय था जब हमारे देश में बने हुए औद्योगिक मालों से दुनिया के बाजार पटे हुए थे लेकिन आज दुनिया के बाजार और देशों के माल से तो पटे ही हैं, हमारे देश में दुनिया के दूसरे देशों से माल कुछ तो मंगाया जाता है और कुछ चोरी छिपे आकर भरा पड़ा हुआ है। हमें अपनी आवश्यकता के लिए उन सामानों के निर्माण की दिशा में जो गांव गांव में उद्योग-धन्धे बिखरे हुए थे जिनके द्वारा उन मालों को तैयार करके काम चलता था, उन नये साधनों के द्वारा या पुराने जो साधन हैं उनमें सुधार ला करके व्यापक पैमाने पर तैयार करवाना चाहिए जिससे देश की जरूरत पूरी हो सके। जो उद्योग धन्धे अभी तक खड़े किए गए हैं वह बड़े-बड़े शहरों के सन्निकट या बड़े-बड़े शहरों में तैयार किए गए हैं। आज गांव इस मामले में बहुत दूर पड़ गए हैं। एक तरफ जहां खेती की उपेक्षा की गई, इस दृष्टि से गांव पिछड़े रह गए वहां औद्योगिक दृष्टि से भी उनकी उपेक्षा की गई और आज गांव एकदम कटे हुए हैं, यद्यपि देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गांवों में बिखरा हुआ है। यह उद्योग धन्धे गांवों में तभी पनप सकते हैं, जब वहां बिजली पहुंचाई जाय। बिना बिजली के आज किसी उद्योग धन्धे का पनप पाना और बड़े कारखानों के मुकाबिले में ठहर पाना मुश्किल है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन गांवों में जहां पर इस तरह के उद्योग-धन्धे चाहे पुराने हों चाहे नई संभावना वाले हों वह अधिक से अधिक खड़े किए जायं। उसके लिए जब तक बिजली वहां नहीं पहुंचती है तब तक काम ठिकाने से नहीं हो सकता। यही नहीं अगर गांवों को ऊपर उठाना है, उनका विकास करना है, जिनके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है, तो वहां पर यातायात के साधन ले जाने होंगे। उन गांवों को पक्की सड़कों से, रेलवे से जोड़ना होगा, तभी यह उद्योग धन्धे वहां पनप पाएंगे और तभी जो गांवों के लोग बड़ी तेजी से शहरों की तरफ चले आ रहे हैं अपनी रोजी की तलाश में वह वहां रुक सकेंगे और जो इतनी बड़ी भीड़ शहरों की तरफ चली आ रही है उस समस्या का समाधान भी हो सकेगा। इसलिए इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं कि छोटे-छोटे धन्धों का विकेन्द्रीकरण किया जाय। उनको छोटे छोटे कस्बों में गांवों में जहां आसानी से कच्चा माल मिल सकता है या जहां आसानी से कच्चा माल पहुंच सकता है वहां लगाया जाय। जहां मजदूरों की सुविधा है, काम करने वाले आसानी से मिल सकते हैं वहां इन उद्योग धन्धों को पहुंचाया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछली जो योजनाएं बनीं उसमें जैसे खेती की उपेक्षा की गई और उसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ा कि अरबों रुपये का गल्ला प्रति वर्ष हमको मंगाना पड़ रहा है और अब सरकार का ध्यान गया है अन्न के उत्पादन की तरफ, खेती के विकास की तरफ, उसी तरह से जो पिछली योजनाएं बनीं, उसमें छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। अगर छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की तरफ सरकार का ध्यान गया होता तो जो देश में इतनी भीषण बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई है वह शायद इस तरह न आती। महात्मा गांधी जिनके नेतृत्व में देश को आजादी मिली, जिनके नेतृत्व में देश ने बिना खून बहाए, अहिंसात्मक ढंग से आजादी प्राप्त की और दुनिया में एक मिसाल कायम की, उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में ग्रामोद्योगों को प्रमुख स्थान देने की तरफ ध्यान दिलाया था और उसी के लिए उन्होंने स्वराज्य के साथ साथ उद्योग धन्धों को प्रमुख स्थान पर रखा था। लेकिन आजादी के बाद हम लोग गलतफहमी में पड़ गए। उसका नतीजा यह हुआ कि खादी ग्रामोद्योग जैसी चीज जिस पर बड़ा बल दे कर उसे गांव गांव में बिखेर देना चाहिए था, जिसके लिए पूरी शक्ति लगानी चाहिए थी, उसकी तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

वह नहीं दिया गया। उसका काम यद्यपि आज भी सराहनीय है, जितने बेकार लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको कोई काम नहीं दिया जा सकता, जो अनाथ हैं, निर्बल हैं, उनको जितना काम वह देता है, उतना दूसरा कोई कल कारखाना नहीं देता है। लेकिन जितना उस पर पैसा लगना चाहिये, सरकार नहीं लगा रही है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि उस को अधिक से अधिक रुपया दे कर इन उद्योग धन्धों को जो ग्रामों में बिखरे हुए हैं और जो आज अपनी मौत मर रहे हैं, उनको ताकत दें, शक्ति दें और उनको उठायें। जब तक गांवों के इन उद्योग-धन्धों को नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक देश का विकास, देश की आजादी अधूरी रह जाती है। इस लिये मैं चाहूंगा कि ग्रामीण उद्योग धन्धों पर अधिक से अधिक ध्यान दे कर, उनके कामों के लिये अधिक से अधिक सहूलियतें पैदा करके, उनकी कठिनाइयों को दूर करके, उनको विकसित होने का अवसर दें। आशा है माननीय मंत्री महोदय इसमें सहयोग देंगे।

कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़ कर उत्तर प्रदेश का सारा हिस्सा आज गरीबी से पीड़ित है। वहां पर कोई भी छोटे उद्योग धन्धे नहीं खोले गये, जिसका नतीजा यह है कि लोग अपनी छोटी-छोटी खेती से किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। वहां के लोगों की सन्तोषी मनोवृत्ति है, वे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, यद्यपि जब जब समय आया है, तब तक उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रदर्शन किया है – चाहे 1957 का गदर हो, चाहे 1942 का आन्दोलन हो, चाहे स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई हो, वे हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन दुख यह है कि सारे देश का विकास हो रहा है, लेकिन वह क्षेत्र आज भी पिछड़ा पड़ा हुआ है। वहां के लोग बड़े धैर्य के साथ सरकार की तरफ निगाह लगाये हुए हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर बिजली का साधन अधिक से अधिक दिया जाय, छोटे-छोटे उद्योग धन्धे वहां पर पनपाये जायं। किसी समय वहां के उद्योग धन्धे देश में अपना स्थान रखते थे, लेकिन आज वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और उनके लिये पर्याप्त साधन जुटाये, जिससे वहां के लोग अपनी जीविका कमा कर अपना जीवन अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली): सभापति महोदय, यहां पर बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, जिनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक खास बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूं। हमारी सब पार्टीज या ज्यादातर पार्टीज देश में सोशलिज्म की बातें कर रही हैं, मुझे इससे बहुत खुशी है। चाहे हमारे मधु लिमये जी का सोशलिज्म हो या फखरुद्दीन साहब का सोशलिज्म हो, चाहे किसी का भी सोशलिज्म हो, लेकिन मैं एक सवाल उन से पूछना चाहती हूं – सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज पूरा खाना भी नहीं मिलता है। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पूरा काम नहीं

17·18 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मिलता है, जो बेकार हैं और इनमें से 15 परसेन्ट ऐसे हैं जो एजूकेटेड अनएम्पलायेड हैं। मैं अपने समाजवादी मित्रों से पूछना चाहती हूं – यदि इसी तरह से चलता रहा, तो क्या आप 5-10 सालों में इन को काम दे सकेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं नीड-बेस्ड वेजेज भी नहीं माँगती, मिनीमम वेज भी नहीं मांगती, मैं सिर्फ इतना मांगती हूं कि हमारे देश में भारतवासियों को सिर्फ राइट-टु-वर्क दे दें। अगर आप इतना कर दें तो इस देश की जनता को अवश्य महसूस होगा कि देश में सोशलिज्म आ गया है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? स्लोगन से नहीं हो सकता है, बड़े बड़े लोगों

को क्रिटिसाइज करने से नहीं हो सकता है, इसके लिये आप को बड़े बड़े ठोस कदम उठाने होंगे। आज हमारे देश में जो तरीका पिछले 20 सालों से चला आ रहा है – मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं, 1963 में यहां पर पं० जवाहर लाल नेहरू ने इतने सालों की प्रोग्रेस और प्लानिंग के बाद क्या बताया था ? उन्होंने कहा था जिस तरह से हम आज तक चलते आ रहे हैं, अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो हमारे देश का भविष्य और हमारे देश की रोजी-रोटी का सवाल हम कभी हल नहीं कर पायेंगे।

तो मैं जानना चाहती हूं कि आज की जो स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए अगली प्लानिंग में स्माल स्केल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और खास कर के खादी ऐन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज के बारे में कितनी मदद देना चाहते हैं उसको डिसेन्ट्रलाइज करके ताकि अधिकांश लोग जोकि देहातों में रहते हैं उनको काम मिल सके—यह हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है। हम सोशलिस्ट हैं इसलिए यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि सोशलिज्म की बात हम देहातों में उन लोगों के घरों तक ले जायं वरना फिर प्लानिंग में रखा ही क्या है ? मैं एक छोटी सी बात करूं कि जहां तक खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात है उसके खिलाफ एक ऐन्टी ग्रुप चलता है और यह कोई नया बात नहीं है। गांधी जी ने जो कहा था उसको छोड़ दीजिए क्योंकि हो सकता है किसी को उन पर श्रद्धा हो या न हो लेकिन तामिलनाडू में जो डी० एम०के० की सरकार है उसने सोचा कि गांधी जी का प्रोग्राम छोड़ दो क्योंकि वह पुरानी बातें हैं लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर उन बातों को डिस्कार्ड करते हैं तो बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे तो फिर उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। इसीलिए मैं जानना चाहती हूं कि क्या हमारी प्लानिंग में कोई ऐसा स्थान है जिससे कि हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, स्माल स्केल इंडस्ट्री है या खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्री है उसकी तरफ ज्यादा जोर लगे ? मुझे पता है कि प्लानिंग कमीशन इन बातों में थोड़ा हेसिटेट करता है लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि प्लानिंग कमीशन क्या कोई सुपर सरकार है ? अगर हमें देश में सोशलिज्म को लाना है तो फिर जितनी ही तेजी से हम उसको लागू करें उतना ही अच्छा है। मैं समझती हूं कि हमारे देश में खादी का अलग सेक्टर बना दें तभी हो सकता है वरना बड़ी इंडस्ट्रीज में तो दस हजार रुपया लगाने पर कहीं एक आदमी को काम मिलता है फिर बड़ी इंडस्ट्री लगाने से कोई जादू नहीं हो सकता है। इस देश के लोगों को काम देने के लिए सोशलिज्म लाना है और गरीबी को दूर करना है। आज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस देश में 17 करोड़ अन्डर एम्पलायमेन्ट है तो उनका क्या भविष्य होगा ? तो इसके लिए क्या आप कोई रिजर्वेशन आफ प्रोडक्शन करना चाहते हैं या नहीं ? आप खादी ऐंड विलेज इन्डस्ट्री, हैंडलूम और एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को पैसा दें और पूरी पूरी सपोर्ट दें— मैं इसकी मांग कर रही हूं।

17·23 hrs.

STATEMENT RE : CONDITION OF M. PS INJURED IN THE POLICE LATHI CHARGE IN DELHI ON 6TH APRIL, 1970

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Mr. Deputy-Speaker, I have ascertained the present condition of Shri Raj Narain and Shri George Fernandes from the All India Institute of Medical Sciences.

Shri Raj Narain was transferred to the Medical Institute Hospital on 8 April from the Safdarjung Hospital. He had sustained a fracture on the left foot. The leg below the knee has been put in plaster. A rubber heel has been fixed on the plaster and Shri Raj Narain is being encouraged to walk with the aid of a walking stick. His general progress is reported to be satisfactory.

Shri George Fernandes was admitted to the Institute Hospital on 14 April. He is being given symptomatic treatment and general investigations are also being made.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): When Shri George Fernandes was admitted to the Willingdon Nursing Home, we all saw him. At that time, as a layman—I am not a doctor nor a compounder I saw that he was very badly